E-Paper : www.goodluckpublications.com, • www.vbslive.in
हिंदी दैनिक
गुवाहाटी, नई दिल्ली, शिमला और जम्मू से एकसाथ प्रकाशित

विकसित भारत समाचार

राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

वर्ष : 11 | अंक : 246 | गुवाहाटी | मंगलवार, 8 अप्रैल, 2025 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

एडीआर रिपोर्ट : चंदों से मालामाल हुई भाजपा पेज 2
वक्फ संशोधन विधेयक से मुस्लिम आबादी के हाशिए पर पड़े और वंचित... पेज 3
न्याय के तराजू पर भी वक्फ बिल जब तुलेगा तो सही दिशा पकड़ेगा : मंत्री अर्जुन... पेज 5
इंटर मियामी को टोरंटो एफसी ने 1-1 की बराबरी पर रोका पेज 7

घरेलू रसोई गैस हुई महंगी उपभोक्ताओं की जेब पर असर

पेट्रोल और डीजल पर भी बढ़ी एक्साइज ड्यूटी

नई दिल्ली। आम जनता को महंगाई के मोर्चे पर एक और झटका लगा है। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ गई हैं। घरेलू गैस सिलेंडर और उज्जवला योजना के तहत मिलने वाले सिलेंडर पर 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को वितरण कंपनियों की ओर से रसोई गैस या एलपीजी की कीमत में 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी किए जाने का एलान किया। मंत्री ने कहा कि उज्ज्वला और सामान्य श्रेणी के ग्राहकों दोनों के लिए गैस की कीमत में इजाफा किया गया है। नई कीमतें आज आधी रात से लागू हो जाएंगी। सामान्य उपभोक्ताओं के लिए 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 803 रुपए से बढ़कर 853 रुपए हो -शेष पृष्ठ दो पर

लूट, वसूली, हेराफेरी... सब मोदी सरकार के पर्याय बन चुके हैं : कांग्रेस

नई दिल्ली। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को बताया कि रसोई गैस या घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है। सब्सिडी वाले और सामान्य श्रेणी के ग्राहकों दोनों के लिए कीमत में बढ़ोतरी की गई है। अब इसको लेकर विपक्ष सरकार पर -शेष पृष्ठ दो पर

पंचायत चुनाव : 2026 के विस चुनावों से पहले एक राजनीतिक परीक्षा

गुवाहाटी। असम में छह साल बाद पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य में पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा ने स्थानीय स्तर के चुनावों के लिए माहौल तैयार कर दिया है, जिसे मतदाताओं के राजनीतिक मूड का संकेतक माना जा रहा है। असम में पंचायत चुनाव 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर और भी महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, इस बार पंचायत चुनाव एक शर्त के साथ आ रहे हैं: असम राज्य चुनाव आयोग ने आदेश दिया है कि गांव पंचायत चुनाव में लड़ने वाले उम्मीदवारों को किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रतीक का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। यह निर्णय स्वशासन को गैर-राजनीतिक प्रकृति का और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखने के उद्देश्य से लिया गया था। हालांकि इस कदम से राजनीतिक दलों की प्रत्यक्ष भागीदारी सीमित हो गई है, जो वे विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी माहौल को परखने के लिए चुनावों का उपयोग करके करना चाहते थे, लेकिन इससे उनकी भागीदारी पूरी तरह समाप्त नहीं हो गई है। राजनीतिक दल अभी भी आंचलिक पंचायत और जिला पंचायत सीटों के लिए उम्मीदवारों को प्रायोजित कर सकते हैं, जहां पार्टी संबद्धता स्पष्ट होगी। चुनाव दो चरणों में 2 मई और 7 मई को होने वाले हैं, जिसके परिणाम 11 मई 2025 को घोषित किए जाएंगे। असम में तीन स्तरीय पंचायत प्रणाली है, जिसमें 181 आंचलिक पंचायतें, 27 जिला पंचायतें और 2,193 गांव पंचायतें हैं। इसका मतलब है कि 21,930 गांव पंचायत सीटों पर गैर-राजनीतिक मुकाबला होगा, जबकि आंचलिक और जिला पंचायत चुनावों में राजनीतिक समर्थन मिलेगा। लगातार दो कार्यकाल से सत्ता में रही सत्तारूढ़ भाजपा पहले से ही चुनावी मोड में है। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा आक्रामक तरीके से कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, जिनमें से कई सीधे गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को लक्षित करती हैं। ओरुनोदोई कल्याण योजना के तहत वित्तीय सहायता बढ़ाकर 1,400 रुपए प्रति माह करने से लेकर छात्रों के लिए 300 रुपए मासिक ट्यूशन फीस सब्सिडी शुरू करने तक, इन उपायों को मतदाता समर्थन को मजबूत करने के कदम के रूप में -शेष पृष्ठ दो पर

इसरो अध्यक्ष ने सीएम को असमसैट प्रक्षेपित करने में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया

नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने सोमवार को इसरो अध्यक्ष वी. नारायणन से मुलाकात की और असम के अपने उपग्रह प्रक्षेपित करने के दृष्टिकोण पर चर्चा की। यहां असम हाउस में इसरो अध्यक्ष के साथ बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के इन-स्पेस (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र) के सहयोग से अपना स्वयं का उपग्रह असमसैट बनाने के असम सरकार के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। डॉ. शर्मा ने चुटकी लेते हुए कहा कि असमसैट महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन और कृषि, आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचे के -शेष पृष्ठ दो पर

मुख्यमंत्री से एनएचआईडीसीएल के एमडी व केंद्रीय उर्वरक सचिव ने की मुलाकात

नई दिल्ली/गुवाहाटी (हि.स.)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा से सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम (एनएचआईडीसीएल) के प्रबंध निदेशक डॉ. कृष्ण कुमार ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने असम में एनएचआईडीसीएल के तहत चल रही राजमार्ग परियोजनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ शर्मा ने प्रबंध निदेशक डॉ कृष्ण कुमार से निर्माणाधीन राजमार्ग और पुल परियोजनाओं में तेजी लाने का भी अनुरोध किया, जिसमें असम में धुबड़ी और मेघालय में फूलबाड़ी को जोड़ने वाला ब्रह्मपुत्र नद पर 19.28 किलोमीटर लंबा 4-लेन पुल, 25 हजार करोड़ रुपए की लागत वाली गुवाहाटी-सिलचर एक्सप्रेस वे, नुमलीगढ़ गोहपुर अंडर वॉटर टनल और बाइहाटा चारियाली से तेजपुर और गोहपुर से कुलजन तक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार शामिल है। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री और एनएचआईडीसीएल के प्रबंध निदेशक ने असम और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में यात्रा -शेष पृष्ठ दो पर

सुप्रभात

मनुष्य का जीवन इसलिए है कि वह अत्याचार के खिलाफ लड़े।
-**सुभाषचंद्र बोस**

25 को गुवाहाटी में फिर से शुरू करेंगे सीमा वार्ता : के सपदांगा

एजल। मिजोरम के गृह मंत्री के सपदांगा ने कहा कि दशकों पुराने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए मिजोरम और असम के बीच आधिकारिक स्तर की वार्ता का एक नया दौर 25 अप्रैल को गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। सपदांगा के अनुसार, आगामी चर्चाओं का प्रस्ताव असम सरकार द्वारा शुरू किया गया था, और मिजोरम ने सैद्धांतिक रूप से इसमें भाग लेने पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मिजोरम प्रतिनिधिमंडल के 24 अप्रैल को एजल से रवाना होने की उम्मीद है। मिजोरम के गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित कार्यक्रम को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिल गई है, लेकिन -शेष पृष्ठ दो पर

राज्य सरकार सस्ती और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देगी : सीएम

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार किफायती और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें चिकित्सा बुनियादी ढांचे के विस्तार और स्वास्थ्य पेशेवरों को पोषित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर, मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सरकार के ध्यान की पुष्टि की। शर्मा ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस पर, हम उन सभी लोगों के प्रति अपनी गहरी प्रशंसा की पुष्टि करते हैं जो हमारे समुदाय को स्वस्थ रखने के लिए अक्सर कर्तव्य से परे कड़ी मेहनत करते हैं। हम स्वास्थ्य सेवा संस्थानों के निर्माण, स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को पोषित करने और सस्ती स्वास्थ्य सेवा को सार्वभौमिक बनाने के लिए संसाधनों को प्राथमिकता देने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य भर में 23 मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं और अगले साल तीन और कॉलेज- दरंग, होजाई और हैलाकांदी में शुरू किए जाएंगे। पिछली सरकारों से इसकी तुलना करते हुए शर्मा ने बताया कि असम में लंबे समय तक केवल तीन मेडिकल कॉलेज थे। मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा में विकास पर भी प्रकाश डाला और कहा कि लगभग हर -शेष पृष्ठ दो पर

ममता ने उठाए एससी के फैसले पर सवाल, जताई साजिश की आशंका

कोलकाता (हि.स.)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य संचालित स्कूलों में 25,753 शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों की नियुक्तियों को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने इस फैसले के पीछे किसी *खेल* की आशंका जाहिर करते हुए कहा कि कुछ ताकतें पर्दे के पीछे से षड्यंत्र कर रही हैं। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में नौकरी गंवाने वाले लोगो के एक बड़े समूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या इस फैसले के पीछे कोई खेल हुआ है? किसने पर्दे के पीछे से यह खेल रचा? मुख्यमंत्री ने -शेष पृष्ठ दो पर

न्यूज गैलरी

अमेरिकी टैरिफ विवाद के बीच शेयर बाजार में गिरावट कांग्रेस का सरकार वार

नई दिल्ली (हि.स.)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दुनिया के अनेक देशों के विरुद्ध घोषित किए गए नए टैरिफ (आयात कर) का प्रभाव दुनिया भर में दिखाई देने लगा है। भारत के शेयर बाजार में भी तेज गिरावट देखने को मिल रही है। इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कांग्रेस पार्टी ने सोमवार -शेष पृष्ठ दो पर

मणिपुर में भाजपा नेता के घर को भीड़ ने लगाई आग

इंफाल। मणिपुर में भाजपा नेता को वक्फ संशोधन कानून का समर्थन करना भरी पड़ गया। भीड़ ने उनके घर को आग के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मणिपुर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष असकर अली ने वक्फ संशोधन कानून का समर्थन किया था। इससे खफा भीड़ ने यह कदम उठाया है। घटना रविवार रात को थौबल जिले के लिलोंग में हुई है। अधिकारियों के मुताबिक असकर अली ने सोशल -शेष पृष्ठ दो पर

असम में पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस में कलह, प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की मांग

नई दिल्ली। असम में पंचायत चुनाव में अब कुछ ही हफ्ते बचे हैं। इस बीच, कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कलह सामने आई है। असम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का एक वर्ग राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहा है और इसको लेकर नई दिल्ली में अभियान चलाया जा रहा है। धुबड़ी लोकसभा क्षेत्र से सांसद रकीबुल हुसैन, विधायक वाजिद अली चौधरी, आफताबुद्दीन मुल्ला, खलीलुर रहमान, रकीब खान, अब्दुल खांडेकर समेत राज्य के अन्य असंतुष्ट कांग्रेस नेता नेतृत्व परिवर्तन की मांग को लेकर नई दिल्ली में मौजूद हैं। असम कांग्रेस के सूत्रों ने सोमवार बताया कि प्रदेश कांग्रेस समिति के कम से कम नौ वरिष्ठ नेता मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष भूपेन बोरा को हटाने की मांग को लेकर नई दिल्ली में -शेष पृष्ठ दो पर

बेगूसराय में राहुल गांधी की पद यात्रा महज 24 मिनट में हुई समाप्त

पटना/बेगूसराय (हि.स.)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बेगूसराय में पदयात्रा महज 24 मिनट में खत्म हो गई। वह कन्हैया कुमार की *पलायन रोको और नौकरी दो* यात्रा में शामिल होने आए थे। इसके बाद राहुल गांधी पटना के लिए रवाना हो गए। राहुल गांधी का बेगूसराय में 11 बजे से लेकर 11:45 बजे तक कार्यक्रम तय था। इस दौरान उन्हें पदयात्रा में शामिल होने के साथ ही नुक्कड़ सभा को भी संबोधित -शेष पृष्ठ दो पर

सऊदी ने भारत-पाकिस्तान समेत 14 देशों का वीजा किया बैन

रियाद। सऊदी अरब ने सुरक्षा कारणों और हज यात्रा के संचालन को बेहतर बनाने के लिए 14 देशों के नागरिकों के लिए वीजा पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, इराक, नाइजीरिया, जॉर्डन, अल्जीरिया, सूडान, इथियोपिया, ट्यूनीशिया, यमन और एक अन्य देश शामिल हैं। यह कदम सऊदी अरब द्वारा हज यात्रा के दौरान सुरक्षा को सुनिश्चित करने और अवैध प्रवास को रोकने के लिए उठाया गया है। सऊदी अधिकारियों का कहना है कि कई विदेशी नागरिक हज, उमराह या व्यापारिक यात्रा के बहाने देश में प्रवेश करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य अवैध रूप से -शेष पृष्ठ दो पर

वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा-

उचित समय पर विचार किया जाएगा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उचित समय पर विचार करेगा। कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और ए एम सिंघवी ने मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया। अधिवक्ताओं ने मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। पीठ में न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि याचिकाओं पर उचित समय पर सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ (संशोधन) विधेयक की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं दायर की गई हैं। इसे 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्ला खान ने अपनी-अपनी याचिकाएं दायर की हैं। जमीयत उलमा-ए-हिंद ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इसमें दावा किया गया है कि यह मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की एक -शेष पृष्ठ दो पर

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
86382-00107

MURTI AVAILABLE

Available all kinds of Marble & White Metal Murties, Ganesh Laxmi, Radha Krishna, Bishnu-Laxmi, Hanuman, Maa Durga, Saraswati, Shivling, Nandi etc. **ARTCLE WORLD,** S-29, 2nd Floor, Shoppers Point, Fancy Bazar, Guwahati-01, **Ph. : 94350-48866, 94018-06952**

ड्रग्स के साथ युवक गिरफ्तार

गुवाहाटी (हिंस)। राजधानी बशिष्ठ थाना पुलिस ने सोमवार को कोइनाधारा में ड्रग्स के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने एक सूचना के आधार पर कोइनाधारा में ड्रग्स तस्करी के आरोप में साहिद हुसैन उर्फ लालू (28) को गिरफ्तार किया है। लालू कामरूप जिला के हाजो थानांतर्गत हाजो मुस्लिमपट्टी गांव का रहने वाला है।

एडीआर रिपोर्ट : चंदों से मालामाल हुई भाजपा

कांग्रेस की कमाई में 252 प्रतिशत की वृद्धि

नई दिल्ली। केंद्र में सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का जलवा लगातार बरकरार है। चंदे को लेकर भाजपा की लोकप्रियता बनी हुई है। उसे इस साल 2243 करोड़ रुपए से अधिक का फंड मिला। फरवरी में दिल्ली चुनाव में शिकस्त का सामना करने वाली आम आदमी पार्टी (आप) को खासा घाटा हुआ है और उस पिछले साल की तुलना में इस बार 70 फीसदी तक चंदा मिला। 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस को चंदे के मामले में 252 फीसदी की वृद्धि हुई है। चुनाव से संबंधित संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारतीय जनता पार्टी को वित्त वर्ष 2023-24 में सबसे अधिक 2,243 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा मिला है जो राष्ट्रीय राजनीतक दलों में सबसे अधिक है। एडीआर ने यह रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपे गए आंकड़ों पर तैयार की है। इन आंकड़ों में राजनीतिक दलों की ओर से 20 हजार रुपए से अधिक के राजनीतिक चंदे की जानकारी दी गई है। एडीआर के अनुसार, राष्ट्रीय दलों को 2,544.28 करोड़ रुपए की राशि कुल घोषित चंदे के रूप में मिले। ये चंदा कुल 12,547 लोगों की ओर से दिए गए। खास बात यह है कि ये आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 199 फीसदी अधिक है। वित्त वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय दलों के कुल दान में 1693.84 करोड़ रुपए की वृद्धि देखी गई, जो पिछले वित्त वर्ष 2022-23 से 199.17 प्रतिशत अधिक आंकी गई। राष्ट्रीय दलों की ओर से घोषित किए गए चंदे में भाजपा को अकेले दान का कुल हिस्से का 88 फीसदी हिस्सा मिला। कांग्रेस को 1,994 लोगों ने दान दिया और उसे 281.48 करोड़ रुपए चंदे के रूप में मिले। कांग्रेस इस लिस्ट में भाजपा के बाद दूसरे नंबर पर है, लेकिन चंदे के मामले में भगवा पार्टी से काफी नीचे है। अन्य राष्ट्रीय दलों आम आदमी पार्टी (आप), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) और नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीईपी) ने कम राशि की जानकारी दी, जबकि बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक एक बार फिर उसे 20,000 रुपए की सीमा से ऊपर कोई दान नहीं मिला। यह पिछले 18 सालों से इसके दाखिल किए गए आंकड़ों के अनुरूप है। इस तरह से बीएसपी को पिछले 18 सालों से 20000 रुपए से ज्यादा के चंदे नहीं मिले। भाजपा को चंदे के रूप में मिलने वाली राशि में लगातार वृद्धि होती जा रही है।

No.DE/BTC/Bodofa UNB/UPSC/2024/2024/12 *Dtd.07/04/2025*

GOVT. SPONSORED RESIDENTIAL COACHING

under the Bodofa UN Brahma Super 50+ Mission – Civil Services (UPSC/APSC)

In pursuance of the Government's notification no: BTC/ Edn (HS) -22/ 2022/Pt-I/ 39 dated Kokrajhar the 7th April, 2025 initiative to support aspiring Civil Services candidates from BTR, **online applications are invited** for the **11-month fully residential coaching** under the **Bodofa UN Brahma Super 50+ Mission – Civil Services (UPSC/APSC)** for the academic year **2025–26**. This initiative, sponsored by the **Government of BTR**, aims to equip meritorious and underprivileged candidates of the region with the best possible training to compete in prestigious Civil Services Examinations.

Seat Allocation Policy:

Out of **100 total seats**, the **top 50** will be selected on a **merit basis for each program**, with **70% reserved for ST candidates of BTR** and **30% for other communities** within BTR. The **remaining 50 seats** will be filled from the waiting list, ensuring **inclusive representation** from **25 diverse communities** of the region, with **2 candidates per community**.

The communities include:

Rabha, Keot, Sutradhar, Sarania Kachari, Barman Kachari, Barman Mandai, Gorkha, Garo, Hajong, Koch Rajbangshi, Nath Yogi, Madahi Kachari, Bhojpuri, Adivasi, Munda, Santal, Kurux, Odiya, Goriya, Jolha, Deshi, Kalita, Bodo, Bengali (including Bengali SC), and Minority Muslim.

Financial Policy:

- The **Government of BTR will bear 75%** of the total cost, including coaching fees, accommodation, and food.
- The remaining **25% of the cost must be paid by selected candidates.**
- **This 25% contribution is mandatory before the commencement of classes.** Failure to deposit the amount on time will result in **cancellation of admission**, and the seat will be allotted to the next candidate on the waiting list.

Eligibility Criteria:

- The applicant must be a **permanent resident of BTR, Assam.**
- Must be a **graduate** (final year students may apply provisionally).
- Selection will be based on a **Prelims and Mains written entrance examination**, followed by an **offline interview and counseling.**

IMPORTANT DATES FOR SUPER 50+ (CIVIL SERVICES)

Activity	Date
Announcement and start of online application	8th April 2025 (Tuesday)
Last date of online application	30th April 2025 (Wednesday)
Issuance of Admit Card (Website)	5th May 2025 (Monday)
Entrance Examination- Prelims (Offline mode)	11th May 2025 (Sunday)
Declaration of Prelims Results and Cut Off (Website)	18th May 2025 (Sunday)
Entrance Examination- Mains (Offline mode)	25th May 2025 (Sunday)
Declaration of Main Results and Cut Off (Website)	8th June 2025 (Sunday)
Interview & Counseling of Shortlisted Candidates (Offline)	15th - 20th June 2025
Commencement of Classes	1st July 2025
Conclusion of Classes	31st June 2026

Sd/-Director of Education
Bodoland Territorial Council, Kokrajhar

पृष्ठ एक का शेष

घरेलू रसोई गैस हुई ...

जाएगी और उज्ज्वला योजना के तहत उपभोक्ताओं के लिए 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 503 रुपए से बढ़कर 553 रुपए हो जाएगी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एलपीजी के प्रति सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की वृद्धि होगी। 500 से यह 550 (पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए) हो जाएगी और अन्य के लिए यह 803 रुपए से बढ़कर 853 रुपए हो जाएगी। यह एक ऐसा कदम है जिसकी हम आगे समीक्षा करेंगे। हम हर 2-3 सप्ताह में इसकी समीक्षा करते हैं। इसलिए, आपने जो उत्पाद शुल्क में वृद्धि देखी है, उसका बोझ पेट्रोल और डीजल पर उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। उस उत्पाद शुल्क वृद्धि का उद्देश्य तेल विपणन कंपनियों को 43,000 करोड़ रुपए की भरपाई करना है। जो उन्हें गैस के कारण नुकसान के रूप में हुआ है...। पुरी ने कहा कि आपने वित्त मंत्रालय की एक अधिसूचना देखी होगी जिसमें कहा गया है कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 2 रुपए की बढ़ोतरी की जा रही है। मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि इसका बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत घटकर लगभग 60 डॉलर प्रति बैरल हो गई है, लेकिन कृपया याद रखें कि हमारी तेल विपणन कंपनियां 45 दिनों की अवधि के लिए स्टॉक रखती हैं। अगर आप जनवरी की बात करें तो उस समय कच्चे तेल की कीमत 83 डॉलर थी, जो बाद में घटकर 75 डॉलर हो गई। इसलिए उनके पास जो कच्चे तेल का स्टॉक है, वह औसतन 75 डॉलर प्रति बैरल है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि तेल विपणन कंपनियां वैश्विक कीमत के हिसाब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करेंगी।

लूट, वसूली, हेराफेरी...

हमलावर हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एलपीजी गैस सिलेंडर की ही कमी रह गई थी, मोदी जी। इस बार तो महंगाई का चाबुक *उज्जवला* की गरीब महिलाओं की बचत पर भी चल गया। उन्होंने आरोप लगाया कि लूट, वसूली, हेराफेरीज्सब मोदी सरकार के पर्याय बन चुके हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि हम इस तरह की मूल्य वृद्धि का कड़ा विरोध करते हैं। यह लोगों पर बोझ है। केंद्र सरकार अपनी जनविरोधी नीतियों के कारण जनविरोधी है। ये मूल्य वृद्धि *रोटी, कपड़ा और मकान* से संबंधित वस्तुओं के लिए है। हम इसकी निंदा करते हैं। पिछले सप्ताह, वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 41 रुपए की कमी की गई थी। मूल्य संशोधन ने रेस्तरां, होटल और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को प्रभावित किया जो दैनिक कार्यों के लिए इन सिलेंडरों का उपयोग करते हैं। आज ही पहले सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर अपना उत्पाद शुल्क भी बढ़ा दिया है, हालांकि, इस बढ़ोतरी का बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा और इसका बोझ तेल विपणन कंपनियों द्वारा उठाया जाएगा। एक आधिकारिक आदेश में बताया गया कि पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर 13 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि शुल्क में वृद्धि अप्रैल 2025 की 8 तारीख को लागू होगी।

पंचायत चुनाव : 2026 के...

देखा जाता है। शर्मा के लिए 2026 का विधानसभा चुनाव उनके राजनीतिक करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीत से असम में सबसे बड़े राजनीतिक नेता के रूप में उनकी स्थिति मजबूत होगी, जिससे राज्य के राजनीतिक परिदृश्य पर उनका नियंत्रण मजबूत होगा। हालांकि, आगामी पंचायत चुनावों में झटका परेशानी का संकेत दे सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पिछले लोकसभा चुनावों में भाजपा के वोट शेयर में गिरावट आई थी, जैसे ऊपरी असम और अल्पसंख्यक बहुल निर्वाचन क्षेत्र। दूसरी ओर, कांग्रेस, जो पिछले एक दशक से राज्य में सत्ता से बाहर है, पंचायत चुनावों को 2026 से पहले अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित करने और सक्रिय करने के अवसर के रूप में देखती है। पार्टी, जो कभी असम के राजनीतिक परिदृश्य पर हावी थी, हाल के वर्षों में आंतरिक संघर्षों और नेतृत्व की चुनौतियों के कारण मजबूत पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रही है। पिछले संसदीय चुनावों में अहम भूमिका निभाने वाले गौरव गोगोई के उभरने से कांग्रेस को उम्मीद की किरण दिखी है। हालांकि, पार्टी को राज्य स्तर पर आंतरिक कलह का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत चुनाव इस बात का संकेत होंगे कि क्या कांग्रेस जमीनी स्तर पर मतदाताओं का समर्थन जुटा पाती है या 2026 में होने वाली बड़ी लड़ाई से पहले बिखरी हुई है। भाजपा-कांग्रेस की लड़ाई से इतर असम जातीय परिषद (एजेपी), रायजोर दल और असम गण परिषद (अगप) जैसी क्षेत्रीय पार्टियां भी नतीजों पर करीबी नजर रखेंगी। अगप जहां भाजपा की सहयोगी है, वहीं एजेपी और रायजोर दल खुद को राष्ट्रीय दलों के लिए व्यवहार्य विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य के बदलते राजनीतिक परिदृश्य में उनकी प्रासंगिकता निर्धारित करने में इन दलों का प्रदर्शन महत्वपूर्ण होगा। असम में आखिरी पंचायत चुनाव 2018 में हुए थे, उस समय मोदी लहर अपने चरम पर थी। भाजपा ने राज्य में अपने बढ़ते प्रभाव को प्रदर्शित करते हुए शानदार जीत हासिल की। हालांकि, उसके बाद से राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है। 2021 के विधानसभा चुनावों में, भाजपा ने सत्ता बरकरार रखी, लेकिन एक नए नेतृत्व ढांचे के साथ, क्योंकि सर्वानंद सोनोवाल ने मुख्यमंत्री के रूप में हिमंत विश्व शर्मा के लिए रास्ता बनाया। 2024 के लोकसभा चुनावों ने मतदाताओं की बदलती भावनाओं को और उजागर किया। जबकि भाजपा नौ संसदीय सीटें हासिल करने में सफल रही, विपक्ष ने चार सीटें जीतकर और उन क्षेत्रों में बढ़त हासिल करके बढ़त हासिल की, जहां पहले भाजपा का दबदबा था।

इसरो अध्यक्ष ने सीएम ...

विकास और सुरक्षा सीमा प्रबंधन और पुलिस अभियानों के लिए समर्पित सेवाओं की मेजबानी के लिए डेटा के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। इसरो अध्यक्ष, जो अपनी पत्नी के साथ थे, ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि उनका संगठन असम के अपने स्वयं के उपग्रह बनाने के दृष्टिकोण को साकार करने में पूर्ण समर्थन देगा। बाद में, सीएमओ, असम ने ट्वीट किया कि एचसीएम डॉ. @हिमंताविश्व ने इसरो के चेयरमैन वी. नारायणन के साथ एक आकर्षक बैठक की, जिसमें असम के अपने स्वयं के उपग्रह को लॉन्च करने के दृष्टिकोण पर चर्चा की गई, जिसका उद्देश्य बाढ़ प्रबंधन, नीति नियोजन और सीमा निगरानी को बढ़ाना है। इसरो ने इस महत्वाकांक्षी पहल को साकार करने में पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया है। एचसीएम ने इसरो के शानदार काम की सराहना की और इसके वैज्ञानिकों को हर भारतीय के लिए एक सच्ची प्रेरणा बताया।

मुख्यमंत्री से एनएचआईडीसीएल...

समय को कम करने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई चल रही परियोजनाओं और नए राजमार्गों और पुलों के निर्माण पर चर्चा की। बाद में माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने पोस्ट में लिखा कि आज राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ. कृष्ण कुमार के साथ मेरी बैठक में, मैंने एजेंसी द्वारा असम में कार्यान्वित की जा रही प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की। जिसमें 25 हजार करोड़ रुपए की गुवाहाटी सिलचर एक्सप्रेस वे, नुमालीगढ़ गोहपुर अंडर वॉटर टनल, बाइहाटा चारियाली से तेजपुर और गोहपुर से कुलजन तक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार शामिल है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय उर्वरक विभाग के सचिव रजत कुमार मिश्रा से भी मुलाकात की और नामरूप में स्थापित किए जाने वाले नए उर्वरक संयंत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने लिखा कि हम नामरूप में ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) में ब्राउनफील्ड अमोनिया कॉम्प्लेक्स के समयबद्ध पूरा होने को सुनिश्चित करने के लिए सही रास्ते पर हैं, जिसे हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। आज दिल्ली में केंद्रीय उर्वरक सचिव रजत कुमार मिश्रा ने इस महत्वपूर्ण पहल की वर्तमान प्रगति पर चर्चा करने के लिए मुझसे मुलाकात की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गत 19 मार्च को 10,601.40 करोड़ रुपए की अनुमानित परियोजना लागत पर एक नया ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

25 को गुवाहाटी में ...

प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की सूची और पूरा कार्यक्रम जैसे बाड़ीक विवरण अभी भी अंतिम रूप दिए जा रहे हैं। फाइल राज्य सरकार को सौंप दी गई है और फिलहाल हरी झंडी का इंतजार है। आगामी बैठक 9 अगस्त, 2024 को एजल में आयोजित मंत्रिस्तरीय वार्ता के चौथे दौर के बाद बातचीत की निरंतरता को दर्शाती है। उस दौर में, मिजोरम के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सपडांगा ने किया था, और असम के दल का नेतृत्व सीमा सुरक्षा और विकास मंत्री अतुल बोरा ने किया था। उस बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में दोनों राज्यों द्वारा प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की पिछली सूची और पूरे यात्रा कार्यक्रम का सम्मान करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई – जिसे अभी भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। फ़ाइल राज्य सरकार को सौंप दी गई है और वर्तमान में हरी झंडी का इंतजार कर रही है। आगामी बैठक 9 अगस्त, 2024 को एजल में आयोजित मंत्रिस्तरीय-स्तरीय वार्ता के चौथे दौर के बाद बातचीत की निरंतरता को चिह्नित करती है। उस दौर में मिजोरम प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सपदांगा ने किया था, जबकि असम के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सीमा सुरक्षा और विकास मंत्री अतुल बोरा ने किया था। उस बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में दोनों राज्यों द्वारा पिछले समझौतों का सम्मान करने और विवादित क्षेत्र में शांति बनाए रखने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। इस बात पर भी सहमति बनी कि दोनों पक्षों के अधिकारी लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए सहयोग करेंगे और विवाद के शेष बिंदुओं की गहन जांच करेंगे। दोनों पक्षों ने 31 मार्च, 2025 से पहले एक और मंत्री स्तरीय बैठक बुलाने पर भी सहमति जताई थी, जो समयसीमा अब समाप्त हो चुकी है। संयुक्त विज्ञप्ति में सीमावर्ती जिलों के पुलिस उपायुक्तों और अधीक्षकों को हर छह महीने में बैठकें आयोजित करने और हर महीने वर्चुअल समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है, ताकि जमीनी स्थिति पर नजर रखी जा सके और स्थानीय स्तर पर विश्वास कायम किया जा सके। वैसे तो सीमा पर तनाव कई सालों से बना हुआ है, लेकिन 26 जुलाई, 2021 को एक घातक झड़प हुई, जब दो राज्य पुलिस बलों के बीच गोलीबाड़ी में असम के पांच पुलिसकर्मी मारे गए – जिसने एक गंभीर मोड़ का काम किया। इस घटना ने शांति के लिए नए सिरे से प्रयास शुरू किया, जिसकी शुरुआत अगस्त 2021 में अतुल बोरा के नेतृत्व में असम के एक प्रतिनिधिमंडल के एजल दौरे से हुई। तब से आधिकारिक वार्ता के चार दौर हो चुके हैं – तीन एजल में और एक गुवाहाटी में। इसके अलावा, मुख्यमंत्री स्तर पर दो दौर की वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई, जहां मिजोरम के पूर्व मुख्यमंत्री जोरमथांगा और उनके असम समकक्ष हिमंत विश्व शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में चर्चा की।

राज्य सरकार सस्ती ...

जिले में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं या निर्माणाधीन हैं। उन्होंने कहा कि हमने होजाई, नगांव, कछार, बोजाली और लखीमपुर में विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं। आज, लगभग हर जिले में एक विश्वविद्यालय है या जल्द ही होगा। बुनियादी ढांचे के मामले में शर्मा ने कहा कि सरकार हर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल बनाने पर काम कर रही है ताकि कनेक्टिविटी में सुधार हो और विकास को बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा कि असम अभूतपूर्व गति से प्रगति कर रहा है। हम देश के विकसित राज्यों में से एक बनने की राह पर हैं। कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत, 78,000 से अधिक उधारकर्ताओं को राज्य के माइक्रोफाइनेंस प्रोत्साहन और राहत पैकेज से लाभ मिला है, जिसका उद्देश्य ऋण-योग्यता बहाल करना और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, सरकार ने राज्य भर में स्कूली छात्रों को 3.23 लाख से ज़्यादा साइकिलें और मेधावी छात्रों को 48,673 स्कूटर वितरित किए हैं। कक्षा 10 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले लगभग 27,000 छात्रों को विभिन्न राज्य शिक्षा योजनाओं के तहत नकद पुरस्कार भी मिले हैं।

असम में पंचायत चुनाव ...

खुलेआम अभियान चला रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, असंतुष्ट नेता चाहते हैं कि लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता और जोरहाट क्षेत्र से मौजूदा सांसद गौरव गोगोई को असम कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया जाए। असम कांग्रेस के नेता वाजिद अली चौधरी ने ईटीवी भारत को बताया कि वो असम कांग्रेस में खाली पड़े कई पदों को भरने के लिए नई दिल्ली में अभियान चला रहे हैं। नेतृत्व में बदलाव की उनकी मांग के बारे में पूछे जाने पर चौधरी ने कहा कि इसका निर्णय पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लेगा। चौधरी ने कहा कि असम कांग्रेस में कई पद खाली हैं। हम इस संबंध में राहुल गांधी सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से मिलना चाहते थे। चौधरी के अनुसार असम कांग्रेस में उपनेता, सचिव सहित कई महत्वपूर्ण पद खाली हैं। उन्होंने कहा कि हमने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने की कोशिश की, लेकिन हमें उनसे समय नहीं मिला। हमने असम के कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र चौधरी को अपनी मांग सौंपी है। असम कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के संबंध में चौधरी ने कहा कि हम आलाकमान के फैसले का पालन करेंगे। असम कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेन बोरा ने नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हालांकि, उन्होंने कहा कि कांग्रेस निश्चित रूप से पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। बोरा ने ईटीवी भारत से कहा कि हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस को पंचायत चुनाव में 1।80 करोड़ से अधिक वोट मिलेंगे। हाल ही में, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व और असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के जिला समिति के अध्यक्षों के बीच नई दिल्ली में मंथन बैठक हुई, जिसमें पंचायत चुनाव से पहले पार्टी की रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई। आगामी पंचायत चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन और संभावना के बारे में पूछे जाने पर वाजिद अली चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हमारे लिए महत्वपूर्ण अवसर है।

बेगूसराय में राहुल गांधी ...

करना था, लेकिन राहुल तय समय से 4 मिनट पहले ही 11.41 बजे ही पटना के लिए रवाना हो गए। कपस्या चौक टाउनशिप गेट के पास होने वाली नुक्कड़ सभा क्यों रद्द की गई, अभी तक इसकी वजह सामने नहीं आ पाई है। राहुल की पदयात्रा के दौरान करीब 10 हजार लोग मौजूद थे। राहुल गांधी को 6-7 डेलीगेट्स से मिलाने का भी प्लान था, लेकिन भारी भीड़ के कारण वो नहीं मिल सके। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हेलिकॉप्टर से बेगूसराय से पटना के लिए निकले हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अल्लावरु और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह पटना में होने वाले राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हैं। वहीं कन्हैया कुमार बेगूसराय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। इसलिए वो पटना में आयोजित राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। चार माह में तीसरी बार राहुल पहुंचे बिहार राहुल गांधी एक दिवसीय बिहार दौरे पर सोमवार सुबह 10 बजे पटना पहुंचे। एयरपोर्ट के बाहर निकलकर पार्टी के नेताओं से मुलाकात की थी। दोपहर एक बजे पटना में राहुल गांधी श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके बाद वह पार्टी की मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे। राहुल गांधी का चार महीने में यह तीसरा बिहार दौरा है। संविधान सुरक्षा सम्मेलन के संयोजक अनिल जय हिंद ने बताया कि एक अप्रैल से सात अप्रैल तक जन्में महापुरुष, जो देश की आजादी के लिए लड़े हैं, उनको विशेष रूप से याद किया जाएगा। आजादी की लड़ाई में शामिल बुद्धु नोनिया की शहादत को याद किया जाएगा। बाबू जगजीवन राम की ऐतिहासिक योगदान के साथ साथ अमर शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी की जयंती पर भी उनका स्मरण होगा।

सऊदी ने भारत-पाकिस्तान...

अधिक समय तक सऊदी अरब में रहना होता है। इस स्थिति से निपटने के लिए सऊदी अरब ने वीजा प्रतिबंध और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा, सऊदी अरब ने 13 अप्रैल तक हज वीजा आवेदन स्वीकार करने का ऐलान किया है। इसके बाद, हज यात्रा समाप्त होने तक कोई नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य हज के दौरान होने वाली भीड़-भाड़ और सुरक्षा संबंधी समस्याओं को रोकना है। इसके साथ ही, सऊदी अधिकारियों ने हज यात्रा के लिए एक डिजिटल गाइड भी लॉन्च किया है, जो 16 भाषाओं में उपलब्ध है, ताकि पर्यटकों को यात्रा के दौरान मदद मिल सके। यह कदम 2024 में हज यात्रा के दौरान हुई 1000 से ज्यादा मौतों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि इस बार सुरक्षा और सुविधाएं बेहतर हो सकें। सऊदी अरब ने चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है और अवैध रूप से देश में प्रवेश करता है, तो उसे 5 साल के लिए सऊदी अरब में प्रवेश से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

ममता ने उठाए ...

मांग की कि सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट करे कि कौन अभ्यर्थी *सही* हैं और कौन *दोषी*। मानवता के नाते हम सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करते हैं कि राज्य सरकार को सही और दोषी अभ्यर्थियों की अलग-अलग सूची सौंपी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट से यह भी जानना चाहेगी कि जब तक नई भर्ती प्रक्रिया नहीं होती, तब तक मौजूदा शिक्षकों के भविष्य को लेकर क्या दिशा-निर्देश हैं। पहले हमें सही अभ्यर्थियों का मामला सुलझाना है। फिर तथाकथित दोषी अभ्यर्थियों के खिलाफ दस्तावेजों और सबूतों की जांच की जाएगी। उन्होंने शिक्षकों से अपील की कि जब तक औपचारिक रूप से नियुक्ति रद्द नहीं होती, वे स्वैच्छिक सेवा जारी रखें। क्या आपको अब तक सेवा समाप्ति का पत्र मिला है? नहीं। तब तक आप स्वैच्छिक सेवा दे सकते हैं। ममता बनर्जी ने घोषणा की कि देश के शीर्ष वकीलों की एक टीम मामले को उच्च स्तर पर आगे बढ़ाएगी। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि जो लोग सेवा में हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करें। हम कानूनी दायरे में रहकर हर जरूरी कदम उठाएंगे। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था को अस्थिर करने के लिए एक साजिश रची जा रही है। उन्होंने खासतौर पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा-माले) के राज्यसभा सांसद और कलकत्ता उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बिकाश भट्टाचार्य को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बिकाश भट्टाचार्य ने ही इस कानूनी लड़ाई की शुरुआत की थी। 2022 से ही यह गंदा खेल खेला जा रहा है। उधर मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग के बाद बाहर निकले इन उम्मीदवारों ने कहा कि वे स्कूल जाते रहेंगे और बच्चों को पढ़ना जारी रखेंगे।

उचित समय पर ...

खतरनाक साजिश है। अपनी याचिका में जमीयत उलमा-ए-हिंद ने कहा है कि यह कानून देश के संविधान पर सीधा हमला है, जो न केवल अपने नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है, बल्कि उन्हें पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता भी देता है। जमीयत ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि यह विधेयक मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की एक खतरनाक साजिश है। इसलिए हमने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। जमीयत उलमा-ए-हिंद की राज्य इकाइयां भी अपने-अपने राज्यों के उच्च न्यायालयों में इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देंगी। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और समस्त केरल जमीयतुल उलमा जैसे संगठनों ने भी शीर्ष अदालत में रिट याचिकाएं दायर की हैं। नये वक्फ कानून का नाम उम्मीद रखा गया है। याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट से इस अधिनियम को असंवैधानिक तथा संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26 और 300-ए का उल्लंघन करने वाला घोषित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। याचिकाओं में प्रतिवादी केंद्र सरकार और विधि एवं न्याय मंत्रालय को इसके प्रावधानों को लागू करने या क्रियान्वित करने से रोकने का अनुरोध किया गया है।

अमेरिकी टैरिफ विवाद के ...

को दुनिया भर में चल रहे व्यापार युद्ध के नतीजों से निपटने में सावधान न रहने पर केंद्र सरकार को घेरा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर एक वीडियो संदेश में कहा कि स्टॉक मार्केट धड़-धड़ करके गिर रहा है। भारतीय शेयर बाजार 2020 में कोविड के बाद से आज सबसे निचले स्तर पर खुले। उन्होंने कहा कि पहले पांच मिनट में ही 19 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। छोटे निवेशक यह बर्बादी देख रहे हैं, लेकिन लोगों को स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की टिप्स देने वाले मोदी और शाह खामोश हैं।

मणिपुर में भाजपा ...

मीडिया पर वक्फ संशोधन कानून का समर्थन किया था। इसके बाद रविवार की रात लगभग नौ बजे गुस्साई भीड़ उनके घर के बाहर जुटी। देखते ही देखते भीड़ ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। कुछ देर बाद घर को आग लगा दी। आगजनी की घटना के बाद असकर अली ने एक नया वीडियो जारी किया है। इसमें उन्होंने अपने पिछले बयान पर माफी मांगी। उन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध भी किया। उधर, इंफाल घाटी के मुस्लिम बहुल इलाकों में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। पांच हजार से अधिक लोगों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। लिलोंग में एनएच-102 पर जाम भी लगाया। अधिकारियों के मुताबिक थौबल के इरोंग चेसाबा में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल साकिर अहमद ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम संविधान की भावना के खिलाफ है। मुस्लिम समुदाय इसे स्वीकार नहीं करेगा। अधिकारियों का कहना है कि इंफाल घाटी के मुस्लिम बहुल इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है।

वक्फ संशोधन विधेयक से मुस्लिम आबादी के हाशिए पर पड़े और वंचित वर्गों के लिए एक काले युग का अंत : भाजपा

भाजपा नेता डॉ. मेहजबीन ने सांसद गौरव गोगोई पर लगाएं गंभीर आरोप

गुवाहाटी (हिंस)। भाजपा की राष्ट्रीय शोध और नीति प्रभारी और प्रमुख महिला नेता डॉ. जफरीन मेहजबीन ने कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक ने भारत की मुस्लिम आबादी के हाशिए पर पड़े और वंचित वर्गों के लिए एक काले युग का अंत कर दिया है। इस सुधारात्मक कानून के माध्यम से वक्फ के नाम पर भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए एनडीए सरकार का कदम सराहना है। भाजपा महिला नेता डॉ. जफरीन मेहजबीन बशिष्ठ स्थित भाजपा के असम प्रदेश मुख्यालय अटल बिहारी वाजपेयी भवन में आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं। डॉ. मेहजबीन ने इस बात पर जोर दिया कि यह कानून न केवल जवाबदेही की दिशा में एक कदम है, बल्कि मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने और सामुदायिक संपत्तियों पर उनके अधिकारों को सुरक्षित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है। इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार, *वक्फ* का अर्थ किसी भी अचल या चल संपत्ति से है जो स्थायी रूप से धार्मिक, धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित है। डॉ. मेहजबीन ने वक्फ के नाम पर भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के इस निर्णायक कदम की सराहना की। डॉ. महजबीन ने कांग्रेस पर वक्फ से संबंधित कानून का इस्तेमाल राजनीतिक तुष्टिकरण के लिए करने का आरोप लगाया। उन्होंने 1995 और 2013 में किए गए संशोधनों का हवाला देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य केवल मुस्लिम वोट बैंक को लुभाना था। इसके बाद के दोनों आम चुनाव 1996 और 2014 में कांग्रेस की चुनावी हार हुई और जनता ने भाजपा के राष्ट्रवादी शासन मॉडल को अपनाया। उन्होंने बताया कि भारत में वक्फ की 37.39 लाख हेक्टेयर जमीन का एक बड़ा हिस्सा अवैध रूप से कब्जा करके मुट्ठीभर स्वार्थी मुस्लिम नेता दुरुपयोग कर रहे है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के इस साहसिक कदम ने इन निहित स्वार्थों की नींव हिला दी है, जिससे विपक्षी दलों में घबराहट पैदा हो गई है और वे अब

भावनात्मक हेरफेर और सांप्रदायिक बयानबाजी का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि असम में लगभग 19 हजार बीघा वक्फ भूमि है, जिसका अनुमानित मूल्य 70 हजार से 80 हजार करोड़ रुपए है। फिर भी बड़े पैमाने पर अतिक्रमण और कुप्रबंधन के कारण राजस्व नगण्य रहा है। डॉ. महजबीन ने जोरहाट के कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर निशाना साधते हुए क्षेत्र की अल्पसंख्यक आबादी के उत्थान के प्रति सांसद की उदासीनता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि गोगोई के कार्यकाल के दौरान सांसद के स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीएलएडी) कोष से एक भी रुपया विकास के लिए आवंटित नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अब वे चुनावी लाभ और मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए वक्फ संशोधन का विरोध करके मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक 25 दिन पहले तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 2013 में वक्फ अधिनियम में राजनीति से प्रेरित संशोधन को आगे बढ़ाया, जिसके तहत दिल्ली के वीवीआईपी क्षेत्र में 123 प्रमुख संपत्तियों को तुष्टिकरण की राजनीति के तहत दिल्ली वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया गया। इस संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता डॉ. मोमिनुल ओवाल ने कहा कि इस संशोधन के माध्यम से वक्फ बोर्ड के गठन का मूल उद्देश्य आखिरकार पूरा हो गया है। असम में वक्फ संपत्तियों को लंबे समय से कुछ विशेषाधिकार प्राद्धस्त्रद्य लोगों द्वारा सोने के अंडे के रूप में माना जाता रहा है। उन्होंने बताया कि जब वक्फ बोर्ड एक समिति के तहत काम कर रहा था, तब राजस्व संग्रह 80-90 हजार रुपए के आसपास था। लेकिन जब से राज्य सरकार ने हाल के वर्षों में प्रत्यक्ष नियंत्रण अपने हाथ में लिया है, राजस्व बढ़कर 2.56 करोड़ रुपए हो गया है। वास्तव में, अकेले वक्फ आय से, सरकार मुख्यमंत्री राहत कोष में 50 लाख रुपए का योगदान करने में सक्षम थी। डॉ. ओवाल ने जोर देकर कहा कि यह स्पष्ट रूप से भाजपा सरकार के वक्फ सुधारों द्वारा लाई गई प्रभावशीलता और पारदर्शिता को प्रमाणित करता है।

बीडब्ल्यूडब्ल्यूए ने मनाया विश्व स्वास्थ्य दिवस, स्वस्थ जीवन के दिए मंत्र

गुवाहाटी (हिंस)। फ्रंटियर मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), पटगांव ने सोमवार को प्रहरी परिवारों के साथ एक विषेश आयोजन कर विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया। इसका उद्घाटन बीएसएफ बीडब्ल्यूडब्ल्यूए की प्रमुख वंदना गौर ने दीप प्रज्वलित कर किया। बीएसएफ वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन (बीडब्ल्यूडब्ल्यूए) के तत्वावधान में पटगांव ने कंपोजिट अस्पताल के सहयोग से एक कार्यक्रम काआयोजन किया गया। इसका उद्देश्य स्वस्थ जीवनशैली के महत्व और जीवनशैली संबंधित बीमारियों से निपटने के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। इस मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रहरी परिवारों को बताया कि जीवन में स्वास्थ्य का कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। एक खुले सत्र में बीएसएफ के जवानों और उनके परिवारों के लिए एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने उच्च रक्तचाप, मधुमेह और मोटापे जैसे सामान्य जीवनशैली से संबंधित बीमारियों की रोकथाम के बारे में जानकारी के साथ स्वस्थ रहने का मंत्र दिया। वक्ताओं ने आहार, शारीरिक गतिविधि और मानसिक स्वास्थ्य के बीच महत्वपूर्ण संबंध पर भी चर्चा की गई। इस सत्र में स्वस्थ आदतें अपनाने के लिए व्यक्तिगत सलाह दी गई। प्रतिभागियों को अपनी सेहत को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया गया। उल्लेखनीय है कि बीडब्ल्यूडब्ल्यूए अपने मिशन के तहत बीएसएफ के परिवारों की भलाई सुनिश्चित करने और उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस और आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सशक्त बनाने में लगा है।

पंचायत चुनाव : बिलासीपाड़ा में कांग्रेस की समीक्षा बैठक आयोजित

धुबड़ी (हिंस)। राज्य में पंचायत चुनाव की तारीख घोषित होते ही सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। हर पार्टी पंचायत में जीत हासिल करने की तैयारी में जुट गई है। इस कड़ी में कांग्रेस पार्टी भी अब सक्रिय हो चुकी है। सोमवार को बिलासीपाड़ा के पद्मश्री प्रतिमा बरुवा पांडे सभागार में कांग्रेस की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आगामी 7 मई को होने वाले पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह बैठक बुलाई गई थी। इस कार्यकर्ता समीक्षा बैठक में धुबड़ी के सांसद रकीबुल हुसैन भी मौजूद थे। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के लिए कोई भी उम्मीदवार किसी नेता को टिकट के बदले पैसे न दे। अगर कोई कांग्रेस नेता टिकट के बदले पैसे लेता है और इसका प्रमाण मिलता है, तो उसके खिलाफ अखिल भारतीय कांग्रेस सख्त कार्रवाई करेगी। सांसद रकीबुल हुसैन ने यह भी कहा कि इस बार के पंचायत चुनाव में भाजपा ने पार्टी का चुनाव चिह्न इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा को भी पता है कि पंचायत चुनाव में भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। इसी वजह से एक साल बाद चुनाव की तारीख तय की गई है। इसके अलावा उन्होंने वक्फ बोर्ड के संबंध में कहा कि भाजपा राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि किस दिन वक्फ बोर्ड पर भाजपा सरकार गिरेगी, वह दिन तय है। रकीबुल हुसैन ने कहा कि वक्फ बोर्ड का मतलब है मुस्लिम समाज द्वारा अल्लाह के नाम पर दी गई जमीन। इसमें हिंदू या मुस्लिम व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता।

इंफैंटिया ने की डिजिटल युग में बच्चों के अधिकारों पर राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत

गुवाहाटी (हिंस)। असम पुलिस ने शिशु मित्र कार्यक्रम के माध्यम से पीआईआईआर फाउंडेशन और यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से गुवाहाटी स्थित एक होटल में सोमवार को डिजिटल युग में बच्चों के अधिकारों पर भारत का पहला राष्ट्रीय संवाद इंफैं टिया आयोजित किया। इस सम्मेलन में बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा सहि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर असम के पुलिस महानिदेशक हरमीत सिंह ने कहा कि हमें इंटरनेट के कई लाभों का लाभ उठाने की आवश्यकता है। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि इसके खतरे हमारे बच्चों को प्रभावित न करें। उन्होंने एक ओर माता-पिता और शिक्षकों के बीच तथा दूसरी ओर बच्चों के बीच विश्वास-आधारित संचार के निर्माण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों और युवाओं के बीच विश्वास खुले संचार का आधार है और यही बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास बच्चों के डिजिटल अधिकारों की रक्षा के लिए एक गंभीर बातचीत शुरू करना है। उन्होंने दर्शकों के प्रत्येक सदस्य से अपने घरों, स्कूलों, समुदायों और पूरे समाज में इस संवाद को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। कार्यक्रम में अभिनेत्री और पेरेंटिंग इन्फ्लुएंसर नेहा धूपिया ने अपने फायरसाइड चैट के माध्यम से

संवाद में गर्मजोशी, प्रामाणिकता और दृढ़ विश्वास पैदा किया। डिजिटल दुनिया में एक मां के रूप में अपनी यात्रा से प्रेरणा लेते हुए नेहा ने आधुनिक माता-पिता द्वारा अपने बच्चों के जीवन को ऑनलाइन साझा करने के लिए सामना किए जाने वाले दबावों के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कैसे असम पुलिस का डांटबिशेयरंट अभियान जिम्मेदार डिजिटल पेरेंटिंग के बारे में एक बहुत जरूरी वैश्विक बातचीत को बढ़ावा देने में सहायक रहा है। नेहा ने कहा कि आपके बच्चे के बारे में सब कुछ ऑनलाइन पोस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ओवरशेयरिंग की बढ़ती संस्कृति और बच्चों की डिजिटल गरिमा की रक्षा करने की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित किया। नेहा ने कहानी को बदलने और बच्चों के अधिकारों, सहमति और गोपनीयता को डिजिटल पेरेंटिंग के केंद्र में रखने की पहल की प्रशंसा की।

महिलाओं की तस्करी में तीन गिरफ्तार

गुवाहाटी (हिंस)। नगर के वशिष्ठ थाना पुलिस ने मानव की तस्करी के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनकेकब्जे से दो महिलाओं को मुक्त कराया है। तीनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि इलाके में महिलाओं की तस्करी में लिप्त लोगों के संबंध में सूचना मिली थी। इस पर पुलिस ने छापा मार करतीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नाइमुद्दीन अली, इनास अली और जाहिदूर इस्लाम के रूप में की गई है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने दो महिलाओं में से एक गुवाहाटी के जालुकबाड़ी और दूसरी को लालमाटी इलाके से छुड़ाया। वशिष्ठ पुलिस के अनुसार नाइमुद्दीन अली अपनी पत्नी को दो लाख रुपए के एवज में एक व्यक्ति को दूसरे राज्य में बेचने की कोशिश कर रहा था। लाख रुपए में बेचने की योजना बना रहा था। पुलिस का कहना है कि महिला तस्करी के गिरोह में और भी कुछ लोग शामिल हो सकते हैं। ऐसे में पुलिस तीनों आरोपियों से सघन पूछताछ कर रही है।

राजस्व मंत्री ने राज्य की बाढ़ तैयारियों की समीक्षा की

गुवाहाटी। माननीय राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री तथा असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) के उपाध्यक्ष केशव महंत ने आज राज्य में आगामी बाढ़ के मौसम की शुरुआत में असम सरकार के विभिन्न विभागों की राज्य स्तरीय बाढ़ तैयारियों की समीक्षा की। असम प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, खानापारा में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में महंत ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जिला आयुक्तों (डीसी) से जिला स्तरीय तैयारियों का जायजा भी लिया। माननीय मंत्री ने बाढ़ के मौसम के दौरान राहत शिविरों के प्रबंधन से संबंधित विभिन्न संवेदनशील मामलों का उल्लेख किया। उन्होंने सभी जिला आयुक्तों (डीसी) से आपदा के दौरान प्रतिक्रिया करने की तुलना में शमन उपायों पर अधिक काम करने का अनुरोध किया। बाढ़ के दौरान हर साल संपत्ति और मानव संसाधन के नुकसान को कम करने के लिए डीसी को जिला स्तर पर शमन उपायों पर पहले से योजना बनानी चाहिए। बाढ़ के दौरान आमतौर पर राहत शिविरों के रूप में उपयोग किए जाने वाले सरकारी बुनियादी ढांचे को शामिल करने वाले प्रस्तावों की पहले से मरम्मत की जानी चाहिए। प्रभावित क्षेत्रों की राजस्व स्तर की मैपिंग, अधिकतम मानव

संसाधन की उपलब्धता, संबंधित राजस्व सर्कल स्तर के अधिकारियों का प्रशिक्षण जैसे मामलों को बाढ़ सीजन से पहले पूरा किया जाना चाहिए। श्रीमती मीनाक्षी दास नाथ, एसीएस, सचिव, राजस्व और डीएम और एडीएल। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एएसडीएमए ने माननीय मंत्री को हितधारकों के साथ आगामी बाढ़ सीजन के लिए राज्य स्तरीय तैयारियों के बारे में समझाया और प्रमुख लेखा शीर्ष (एच/ए) के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए किए गए बजट प्रावधानों पर प्रकाश डाला। श्रीमती नाथ ने एएसडीएमए द्वारा मार्च, 2025 के महीने में पहले से ही आयोजित विषयगत बैठकों की श्रृंखला के दौरान लिए गए निर्णयों के बारे में उपस्थित अधिकारियों को अवगत कराया। विषयगत बैठकों के दौरान बाढ़ प्रतिक्रिया के संबंध में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं : सभी विभाग 1 मई 2025 से पहले अपने क्षेत्र स्तर के पदाधिकारियों के साथ सभी आवश्यक निर्देश, दिशानिर्देश और निर्णय आदि साझा करेंगे। 1 मई से 31 अक्तूबर 2025 तक उत्पादन मोड में। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की टीमें कछार, बारपेटा, बोंगाईगांव, जोरहाट (1 बटालियन एनडीआरएफ द्वारा), सोनितपुर, शिवसागर, डिब्रूगढ़ (12वीं बटालियन एनडीआरएफ द्वारा), 12वीं बटालियन एनडीआरएफ को जोनाई सह-जिले में भी तैनात किया जाएगा, जैसा कि जिलों के साथ आयोजित वीडियो कांफ्रेंसिंग में तय किया गया था। सभी राजस्व मंडलों को मॉडल राहत शिविरों में महिला टास्क फोर्स का गठन करना होगा, ताकि लिंग के आधार पर राहत शिविरों का प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। यूनिसेफ, उपलब्ध मार्गदर्शन की समझ और उपयोग में सुधार के लिए डीडीएमए और जिला स्तरीय लाइन विभागों के ऑनलाइन/ऑफलाइन अभिविन्यास को आयोजित करने के लिए एएसडीएमए का समर्थन करेगा। महिला और बाल विकास विभाग राहत शिविरों में सेवाएं प्रदान करके बाढ़ के दौरान आईसीडीएस सेवाओं को जारी रखेगा। वे राहत शिविरों में स्थापित किए जाने वाले सामुदायिक रसोईघर की आवश्यकता का आकलन करने में डीडीएमए की मदद करेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग संबंधित डीडीएमए के सहयोग से सभी चिन्हित शिविरों का मूल्यांकन करेगा तथा दिव्यांगता समावेशन को बढ़ाने के लिए व्यावहारिक, स्थानीय स्तर पर क्रियान्वित कार्यों की सिफारिश करेगा।

प्रो. अच्युत सामंत को मिलेगा गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म सम्मान

कोकराझाड़ (असम) (हिंस)। गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रस्ट द्वारा कोकराझाड़ टाउन ब्रह्म मंदिर प्रांगण में प्रस्तावित एक समारोह में वर्ष 2025 के लिए 7वां गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म सम्मान उड़ीसा के प्रोफेसर अच्युत सामंत को देने की घोषणा की गई। इस संबंध में ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. अजीत बोड़ो ने सोमवार को जानकारी दी कि इस सम्मान में एक लाख रुपए नगद, पारंपरिक पोशाक, अरणाई, प्रमाण पत्र और स्मृति चिह्न प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार 18 अप्रैल को बर्मा कॉलेज में आयोजित होने वाले गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म की 166वीं जयंती समारोह के अवसर पर प्रदान किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बीटीआर के मुख्य कार्यकारी सदस्य प्रमोद बोड़ो मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रो. अच्युत सामंत कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के संस्थापक हैं। वर्तमान में वे वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।

सनातन हिंदू आर्मी ने राम नवमी उत्सव मनाया

गुवाहाटी (विभास)। सनातन हिंदू आर्मी ने फैंसी बाजार शनि मंदिर चौराहे पर रामनवमी उत्सव का पालन किया। इस अवसर पर दोपहर को भगवा ध्वज पहरा कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी व पूर्व पार्षद महावीर स्वामी ने भारत माता के चित्र के आगे माल्यार्पण कर भगवा ध्वज फहराया। इस अवसर पर उनके साथ सनातन हिंदू आर्मी के प्रमुख मनोज डेका, सचिव सिद्धार्थ पारीक, पार्षद प्रमोद स्वामी और कार्यक्रम संचालक अमित कंसल के अलावा अन्य कई सदस्य उपस्थित थे। शाम को नाम कीर्तन एवं हनुमान चालीसा पाठ के साथ आध्यात्मिक कार्यक्रम किया गया। जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में गुवाहाटी के पुलिस आयुक्त पार्थ सारथी महंत ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर उनके साथ सनातन आर्मी के प्रमुख मनोज डेका, भाजपा नेता मधुराम डेका, जीएमडीके सह आयुक्त मुक्ति डेका, समाजसेवी परेश पारीक, श्याम सुंदर पारीक,

पारीक सभा के अध्यक्ष दिनेश पारीक, हिंदू आर्मी के सचिव सिद्धार्थ पारीक के अलावा कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पार्थ सारथी महंत ने अपने संबोधन में कहा कि रामनवमी हम सिर्फ राम की पूजा के लिए ही नहीं मानते बल्कि रामचंद्र जी के आदर्शों को अपने जीवन में उतरने के लिए मनाते हैं। हम जब सोचते हैं कि धर्म सिर्फ उपासना है, धर्म नीति नियम है। किंतु यदि हम राम के जीवन चरित्र को देखेंगे और उन्होंने जो काम किया उन्हें देखेंगे तो हम समझ जाएंगे की रामचंद्र ने धर्म की व्याख्या व संज्ञा को केवल नीति नियम में ही बांध के नहीं रखे थे। श्री राम के लिए धर्म न्याय था और वह न्याय के पद पर ही चलते थे। वे सत्य, त्याग, ममता के पथ पर चलते थे। धर्म के लिए त्याग जरूरी है। बिना त्याग के धर्म का पालन नहीं हो सकता। हिंदू आर्मी के प्रमुख मनोज डेका ने भी सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आगे आने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ में असंख्य लोगों ने अपना योगदान दिया। असमिया नाम कीर्तन में भी लोगों ने श्री रामचंद्रजी का गुणगान किया।

बरपेटा में पंचायत चुनाव को लेकर अगप भाजपा की हुई बैठक

बरपेटा (असम) (हिंस)। पंचायत चुनाव को लेकर बरपेटा लोकसभा क्षेत्र में असम गण परिषद और भाजपा के गठबंधन के नेताओं की सोमवार को एक बैठक हुई। इस बैठक में पंचायतों में दोनों दलों के बीच चुनाव रणनीति पर चर्चा हुई। बरपेटा राइन क्लब में आयोजित इस बैठक में स्थानीय विधायक एवं राज्य सरकार के मंत्री रंजीत कुमार दास, मंत्री जयंत मल्ल बरुवा और बरपेटा के सांसद फणी भूषण चौधरी उपस्थित रहे। बैठक में अगप नेता और पूर्व सांसद कुमार दीपक दास, बरपेटा जिले के अगप अध्यक्ष और पूर्व विधायक गुनिंद्र नाथ दास, पूर्व विधायक और अगप केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष डॉ. ताराप्रसाद दास ने चुनावी रणनीति के संदर्भ में चर्चा की।

बंगाईगांव में रामनवमी पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित

बंगाईगांव। श्री रामनवमी उत्सव समिति, बंगाईगांव जिला के तत्वाधान में एवं विश्व हिंदू परिषद बंगाईगांव जिला समिति के सहयोग से रविवार को रामनवमी के शुभ अवसर पर पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बोरपाड़ा खेल मैदान में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें भागवत पाठ के पहले मातृ शक्ति द्वारा नाम प्रसंग के अनुष्ठान का आयोजन किया गया था। दोपहर को बौद्धिक कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वयं संघ,उत्तरी असम के सहायक प्रांत प्रचारक श्री दिलीप जी उपाध्याय ने भावनात्मक तथा प्रभावी रूप से भगवान श्री राम के चरित्र के उपर अपनी बातें रखी तथा उन्होंने अपने संबोधन में सनातनी लोगों से प्रभु राम की तरह अपने माता-पिता का आज्ञाकारी होने का आह्वान किया। अपने बुजुर्ग माता-पिता को कभी भी वृधा आश्रम में ना रखें बल्कि उनकी सेवा कर राम की तरह अपने जीवन को भक्तिमय बनाएं। दोपहर 4 बजे राम के रूप में सजे छोटे छोटे बालकों की भव्य आरती के बाद एक विशाल शोभायात्रा निकाली गई जो बोरपाड़ा स्टेडियम खेल मैदान से शुरू होकर शहर का भ्रमण करते हुए बंगाईगांव युनिवर्सिटी के मैदान में समाद्धस्त्रद्य हुई। इस शोभायात्रा में अच्छी संख्या में सनातनी हिंदुओं ने हिस्सा लिया जिसमें पुरुष, महिलाएं तथा बच्चे शामिल थे। पूरा शहर जय श्री

राम के नारों से गूंज उठा। शोभा यात्रा के दौरान रास्ते में मारवाड़ी युवा मंच, बंगाईगांव शाखा, रॉबिन हुड आर्मी आदि कई संस्थाओं तथा व्यक्तिगत तौर पर कई लोगों ने भक्तों के लिए पेयजल एवं शरबत की व्यवस्था की थी। शोभा यात्रा की समाद्धस्त्रद्य पर एक धार्मिक सांस्कृतिक भजन संध्या का आयोजन किया गया जिसमें स्थानीय गायक कलाकार नवीन अग्रवालों ने प्रभु राम के एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में अरूपर्णा राय ने भी भारतनाट्यम के ऊपर नृत्य प्रस्तुत किया। आज के कार्यक्रम के दौरान कई विशिष्ट व्यक्तियों का सम्मान भी किया गया जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम में सहयोग किया। खिचड़ी के प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। उधर बंगाईगांव बड़ा बाजार स्थित श्री राम मंदिर में भी प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया तथा अन्य मंदिरों में भी श्री राम नवमी के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को सफल करने के लिए श्री राम नवमी उत्सव परिचालन समिति के अध्यक्ष मनोज हरलालका एवं सचिव मनोरंजन बनिक्य ने सभी सनातनी लोगों को धन्यवाद दिया।

संपादकीय

न्यूनतम किराए का बड़ा टिकट

न्यूनतम किराया बढ़ोतरी के आयाम और पैगाम के बीच भविष्य की परिवहन अनुशंसा समझी जा सकती है। हिमाचल के यातायात साधनों की सीमित परिपाटी ने यात्री और यात्रा का विवरण बदला है। सडक़ परिवहन पर निर्भरता का आलम यह है कि हर गांव में ट्रैफिक जाम का अलार्म बज रहा है। बहरहाल सुक्खू सरकार ने अपने थैले से न्यूनतम बस किराए की पर्ची निकाल दी यानी अब बस पर बैठ कर उतरने से पहले कम से कम दस रुपए का टिकट तो लगेगा ही। इसे हम आलोचना की दृष्टि से देखें तो विपक्ष के पास खुला मैदान है, लेकिन परिवहन की मांग और इसके प्रबंधन के लिहाज से यह एक आवश्यक कदम था। इससे न केवल निजी बस आपरेटरों की मांग पूरी हो रही है, बल्कि स्थानीय ट्रांसपोर्ट के मायने भी बदल रहे हैं, लेकिन इस फैसले को न्यायोचित ठहराने के लिए बसों के रूट और समय सारिणी के अनुशासन भी निर्धारित करने होंगे। परिवहन अब एक मांग नहीं जीवनशैली की आवश्यकता और यात्रियों के व्यवहार की पुष्टि है। हिमाचल में सार्वजनिक परिवहन की जरूरतें गांव से शहर, शहर से शहर, शहरों के भीतर, अंतरराज्यीय डेस्टिनेशन, धार्मिक दर्शन, पर्यटन व आर्थिकी के विभिन्न पहलुओं से जुड़ती हैं। चामुंडा से वृंदावन बस सेवा की शुरुआत का आयाम अलग है, जबकि चामुंडा से धर्मशाला, पालमपुर, नगरोटा बगवां व कांगड़ा बस सेवा का अभिप्राय अलग है। इन दोनों सेवाओं को अलग-अलग परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। शहरी विकास या नए नगर निगमों के प्रस्ताव को क्या हमने सार्वजनिक परिवहन की बदलती जरूरतों में समझा। क्या नगर निगमों से जुड़े गांवों को ऐसी परिवहन सुविधाओं से जोड़ा ताकि सडक़ों पर वाहनों का दबाव घटे। यात्रा सुविधाजनक, समय के अनुरूप और गतिशीलता के साथ चलाने के लिए परिवहन विभाग को अलग-अलग भौगोलिक, सामाजिक, व्यावसायिक, धार्मिक व पर्यटन मानचित्र बनाने पड़ेंगे। यह महज न्यूनतम बस किराए को पांच से दस रुपए करने की अनुशंसा नहीं, बल्कि यह भी देखना होगा कि ऐसी किराया वृद्धि से एचआरटीसी कैसे आत्मनिर्भर हो पाती है। न्यूनतम किराया वृद्धि के फलक पर अगर कई कारण मौजूद हैं, तो कई निवारण भी पैदा करने पड़ेंगे। कम से कम इससे स्थानीय बस सेवा का नेटवर्क ही स्थापित हो जाए, ताकि जनता के अलावा पर्यटकों को हमेशा टैक्सियों के मुंह मांगे दाम न चुकाने पड़ें। न्यूनतम किराया वृद्धि से पूरा परिवहन क्षेत्र संबोधित नहीं होता, खासतौर पर जहां तक इससे जुड़ी सेवाओं का ताल्लुक है। टैक्सियों की दरें तय न होने के कारण यह परिवहन में माफिया की तरह आपरेट हो रहा है। पर्यटक सीजन का नकारात्मक पहलू टैक्सियों की मनमानी दरें हैं, जबकि महानगरों में भी ओला, उबर तथा ऐसी ही ऑनलाइन परिवहन सेवाओं की उपयोगिता ने निजी वाहनों के उपयोग को घटा दिया है। चंडीगढ़ में अगर किसी को पीजीआई जाना हो या नोएडा-गुडग़ांव से दिल्ली एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जाना हो, तो टैक्सियों के पैमाने किराया वहन करने में समर्थ हैं, जबकि शिमला, मकलोडगंज या मनाली से हवाई अड्डों तक पहुंचना अधिकतम दरों के भी रिकार्ड तोड़ देता है। ऐसे में हर तरह के किराए में एक न्यूनतम सीमा तय हो। रज्जु मार्गों पर भी किराए की सीमा तय होनी चाहिए। मसलन धर्मशाला से मकलोडगंज अगर स्काई-वे सफर से तय करना हो तो एकतरफा 450 रुपए लगते हैं, यह हिमाचल की परिवहन जरूरतों का विकल्प कैसे हो सकता। निजी बसों के लिए न्यूनतम बस किराए की बढ़ोतरी से व्यवसाय को संबल मिलेगा, तो देखना यह होगा कि एचआरटीसी इससे कितना संभल पाती है। जाहिर तौर पर परिवहन निगम की आय के बड़े स्रोत अंतरराज्यीय बस सेवाएं रही हैं, लेकिन प्राइवेट बस आपरेटरों ने वोल्वो जैसी बसें उतार कर अपनी पैठ बना ली है। ऐसे में निगम प्रबंधन को अपनी विश्वसनीयता को लाभकारी बनाने के लिए अंतरराज्यीय बस सेवाओं की उपयोगिता को यात्री संतुष्टि से जोड़ते हुए, इन्हें मांग के अनुरूप बनाना होगा।

सडक़ परिवहन पर निर्भरता का आलम यह है कि हर गांव में ट्रैफिक जाम का अलार्म बज रहा है। बहरहाल सुक्खू सरकार ने अपने थैले से न्यूनतम बस किराए की पर्ची निकाल दी यानी अब बस पर बैठ कर उतरने से पहले कम से कम दस रुपए का टिकट तो लगेगा ही। इसे हम आलोचना की दृष्टि से देखें तो विपक्ष के पास खुला मैदान है, लेकिन परिवहन की मांग और इसके प्रबंधन के लिहाज से यह एक आवश्यक कदम था। इससे न केवल निजी बस आपरेटरों की मांग पूरी हो रही है, बल्कि स्थानीय ट्रांसपोर्ट के मायने भी बदल रहे हैं, लेकिन इस फैसले को न्यायोचित ठहराने के लिए बसों के रूट और समय सारिणी के अनुशासन भी निर्धारित करने होंगे। परिवहन अब एक मांग नहीं जीवनशैली की आवश्यकता और यात्रियों के व्यवहार की पुष्टि है। हिमाचल में सार्वजनिक परिवहन की जरूरतें गांव से शहर, शहर से शहर, शहरों के भीतर, अंतरराज्यीय डेस्टिनेशन, धार्मिक दर्शन, पर्यटन व आर्थिकी के विभिन्न पहलुओं से जुड़ती हैं। चामुंडा से वृंदावन बस सेवा की शुरुआत का आयाम अलग है, जबकि चामुंडा से धर्मशाला, पालमपुर, नगरोटा बगवां व कांगड़ा बस सेवा का अभिप्राय अलग है।

टैरिफ के प्रभाव से अन्य देशों की तुलना में भारत कम प्रभावित होगा

नई टैरिफ जंग में भारत कैसे उभरेगा?

डा. जयंती लाल भंडारी

ट्रंप के नए टैरिफ ऐलान से दुनिया भर के बाजारों और शेयर बाजारों में हाहाकार मच गया है। यद्यपि भारत में सरकार ने संसद में ट्रंप की नई टैरिफ नीति के मद्देनजर घरेलू उद्योगों के संरक्षण की बात कही है, लेकिन अब देश के उद्योग जगत के द्वारा टैरिफ संरक्षण की बजाय वैश्विक प्रतिस्पर्धा व अनुसंधान व विकास (आरएंडडी) पर ध्यान दिया जाना होगा। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत के कुल निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 18 फीसदी रही, जो करीब 77 .5 अरब डॉलर थी, निर्यात की ऐसी ऊंचाई अमेरिका को भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनाती है। अतएव ट्रंप के टैरिफ से भारत के कई प्रमुख निर्यात क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं।

दो अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिकी विनिर्माण को बढ़ावा देना और व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए मित्र और विरोधी दोनों तरह के देशों पर नए पारस्परिक टैरिफ (रेसिप्रोकल टैरिफ) लगाए हैं। भारत पर 26 फीसदी टैरिफ लगाया गया है। ट्रंप के नए टैरिफ ऐलान से दुनिया भर के बाजारों और शेयर बाजारों में हाहाकार मच गया है। यद्यपि भारत में सरकार ने संसद में ट्रंप की नई टैरिफ नीति के मद्देनजर घरेलू उद्योगों के संरक्षण की बात कही है, लेकिन अब देश के उद्योग जगत के द्वारा टैरिफ संरक्षण की बजाय वैश्विक प्रतिस्पर्धा व अनुसंधान व विकास (आरएंडडी) पर ध्यान दिया जाना होगा। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत के कुल निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 18 फीसदी रही, जो करीब 77.5 अरब डॉलर थी, निर्यात की ऐसी ऊंचाई अमेरिका को भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनाती है। अतएव ट्रंप के टैरिफ से भारत के कई प्रमुख निर्यात क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। इनमें टेक्सटाइल और परिधान, ऑटोमोबाइल पाट्र्स, रत्न और आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि उत्पाद शामिल हैं। लेकिन टैरिफ के प्रभाव से अन्य देशों की तुलना में भारत कम प्रभावित होगा। एसबीआई रिसर्च के अनुसार भारत के कुल निर्यात पर प्रभाव 3.3.5 प्रतिशत तक सीमित रह सकता है। इसमें कोई दोमत नहीं हैं कि ट्रंप के टैरिफ जंग में भारत के लिए घरेलू मांग, घरेलू आर्थिक घटक नए व्यापार समझौते और रिकार्ड खाद्यान्न उत्पादन व रिकॉर्ड खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों का निर्यात कारगर हथियार दिखाई दे रहे हैं। निःसंदेह देश में बढ़ते मध्यम वर्ग के कारण खपत भारत में दिखाई दे रही है। देश के उपभोक्ता बाजार को देश का मध्यम वर्ग नई आर्थिक ताकत दे रहा है। देश में आर्थिक सुधारों के साथ ऊंची विकास दर और शहरीकरण की ऊंची वृद्धि दर के बलबूते भारत में मध्यम वर्ग के लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। हाल ही में प्रकाशित दि राइज ऑफ मिडल क्लास इंडिया नामक डॉक्यूमेंट के मुताबिक भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की संख्या तेजी से बढक़र वर्ष 2021 में लगभग 43 करोड़ हो गई है और वर्ष 2047 तक यह संख्या बढक़र 102 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इस वर्ग को 5 लाख से 30 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले परिवारों के रूप में परिभाषित किया गया है। निश्चित

रूप से भारत के मध्यम वर्ग की मुट्ठियों में बढ़ती क्रय शक्ति और जेन जी एवं मिलेनियल्स की आंखों में उपभोग और खुशहाली के जो सपने दिखाई दे रहे हैं, उनके कारण जहां दुनिया के कई देश भारत से आर्थिक और कारोबारी संबंध बढ़ाने के लिए तत्पर हैं, वहीं दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने नामी ब्रांडों के साथ भारत के बहुआयामी उपभोक्ता बाजार में नई रणनीतियों के साथ दस्तक दे रही हैं। निश्चित रूप से भारत डोनॉल्ड ट्रंप की टैरिफ मार से बचने और वैश्विक व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए नए वैश्विक व्यापार समीकरणों के साथ आगे बढ़ रहा है। हाल ही में 26 से 29 मार्च तक नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के वरिष्ठ व्यापार प्रतिनिधियों ने दोनों देशों के बीच 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंचाने के प्रस्तावित व्यापार समझौते की रूपरेखा और संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए सार्थक वार्ता की है। जहां एक ओर सरकार तेजी से मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों की रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। अब जहां नॉर्वे, हंगरी, ग्वाटेमाला, पेरू, चिली के साथ भी शीघ्र ही व्यापार समझौते की बातचीत शुरू की जानी चाहिए, वहीं अब भारत के द्वारा ओमान, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, इजरायल, भारत गल्फ कंट्रीज काउंसिल के साथ भी एफटीए को शीघ्रतापूर्वक अंतिम रूप देने की डगर पर तेजी से आगे बढ़ा जाना होगा। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि जिस तरह पांच साल पहले कोरोना से जंग में देश के खाद्यान्न भंडार देश के हथियार बन गए थे, उसी प्रकार इस समय अमेरिका के टैरिफ की मार के साथ-साथ शुल्क व गैर शुल्क बाधाओं को कम करने से होने वाली किसी भी प्रकार की हानि को कम करने के मद्देनजर देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन और रिकॉर्ड खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद एक मजबूत हथियार दिखाई दे रहे हैं। चूंकि इस वर्ष 2025 में वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन में कमी के आकलन प्रस्तुत हुए हैं, ऐसे में ट्रंप के टैरिफ से भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में होने वाली 3 से 3.5 फीसदी हानि की बहुत कुछ भरपाई खाद्यान्न और कृषि प्रसंस्करण के निर्यात से भी की जा सकेगी। निश्चित रूप से देश में बढ़ता खाद्यान्न उत्पादन और मजबूत होती ग्रामीण आर्थिकी देश की आर्थिक शक्ति बन गई है। निःसंदेह ऐसे मजबूत आर्थिक आधार के बावजूद हमें ट्रंप की टैरिफ चुनौतियों के साथ वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव, व्यापार नीति में अनिश्चितता, अंतरराष्ट्रीय बाजार में जिंसों के दाम और वित्तीय बाजार में अस्थिरता तथा विदेश में व्याप्त आर्थिक निराशावाद के प्रति भी सतर्क रहना होगा। हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि खाद्य कीमतों में तेज गिरावट और कम मुख्य मुद्रास्फीति के कारण नीतिगत दरों में कटौती की गुंजाइश बनती है, किन्तु घटती महंगाई और बढ़ते खाद्य उत्पादन को देखकर सरकार को कृषि क्षेत्र में लंबे समय से पसरी हुई चुनौतियों से नजर हटाने से बचना होगा। निश्चित रूप से ट्रंप के टैरिफ से इस समय देश की आर्थिकी को होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई के साथ भव निःसंदेह भारत के विनिर्माण क्षेत्र को संरक्षण के लिए टैरिफ पर निर्भर रहने के बजाय प्रतिस्पर्धा और कारोबार बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। भारत ने ऐतिहासिक रूप से घरेलू निवेशकों के संरक्षण के लिए ऊंचे शुल्क बनाए रखे हैं। 1991 में उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा की ओर बढ़ाने के लिए उदारीकरण के लाभ मिले हैं। चूंकि टैरिफ प्रतिस्पर्धा से जुड़े हैं, अगर हम टैरिफ की आड़ में रहेंगे तो प्रतिस्पर्धी नहीं बन पाएंगे। हम उम्मीद करें कि भारत 2 अप्रैल को अमेरिका के द्वारा भारत पर लगाए गए 26 फीसदी टैरिफ की चुनौती का मुकाबला करने में सफल होगा। भारत की बढ़ती घरेलू मांग, नए व्यापार समझौते, रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन, बढ़ता खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और बढ़ता कृषि व खाद्य प्रसंस्करण निर्यात और घरेलू आर्थिक घटक भारत के लिए मजबूत और असरकारक आर्थिक हथियार के रूप में उपयोगिता देते हुए दिखाई देंगे। साथ ही उद्योग-कारोबार के द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाए जाने पर भारत टैरिफ की चुनौतियों के बीच वैश्विक कारोबार बढ़ाने के मौकों को भी मुट्ठी में लेते हुए दिखाई देगा।

दृष्टि कोण

देवभूमि की धरा पर चरमपंथ की आहट

राष्ट्र के लिए बलिदान का जज्बा रखने वाला सैन्य पृष्ठभूमि का गढ़ वीरभूमि हिमाचल किसी तारूफ का मोहताज नहीं है। राज्य के सैन्य धरातल पर आतंकवाद को मुहतोड़ जवाब देकर बलिदान हुए मेजर 'संदीप सांखला', कैप्टन 'सुधीर वालिया' 'अशोक चक्र' व लखवीर सिंह 'शौर्य चक्र' तथा सूबेदार प्रेमचंद 'कीर्ति चक्र' जैसे शूरवीरों की दास्तान-ए-सुजात का अक्स नजर आता है। लेकिन पिछले कुछ अर्से से कुछ अलगाववादी ताकतें देश-दुनिया के सबसे शांतमयी राज्यों में शुमार हिमाचल प्रदेश के शांत वातावरण को दुष्प्रभावित करने में लगी हैं। पड़ोसी राज्यों के लोग आस्था की आड़ में स्थानीय दुकानदारों से बदसलूकी कर रहे हैं। अकीदतमंदों के भेस में अलगाववादी नारे लगाकर कानून को ठेंगा दिखाया जा रहा है। इतिहास साक्षी रहा है कि मजहब की बुनियाद पर हिंदोस्तान के बंटवारे से लेकर मुल्क में आगजनी, हिंसा, कट्टरपंथ व अलगाववाद जैसी हिमाकत की तखलीक के पीछे सियासत व मजहबी जमातों ने एक मखसूस किरदार अदा किया है। सियासी हुक्मरानों की तल्ख बयानबाजी तथा मजहबी रहनुमाओं की आग उगलती तकरीरें बुझी राख को भी भडक़ाने की पूरी सलाहियत रखती हैं। मौजूदा वक्त का तनाजुर भी कुछ ऐसा ही है। हिंसा में बेगुनाह इनसानियत का कत्ल हो, आगजनी की लपटों में मजहब जले, तहजीब राख हो, लोगों के आशियाने खाक हों या मासूम यतीम हो जाएं, मगर सियासत की निगाहें सियासी जमीन तराशती हैं। मजहबी जमातें सियासत को अपनी ताकत का एहसास कराती हैं। दूसरी विडंबना यह है कि आतंक के मरकज हमसाया मुल्क पाकिस्तान से सटे सरहदी राज्यों की सीमाएं हिमाचल से लगती हैं। आईएसआई सहित विदेशी खूफिया एजेंसियां भारत में चरमपंथ को बढ़ावा देने में लगी रहती हैं। हिमाचल की सरजमीं पर चरमपंथी तत्वों द्वारा अंजाम दी जाने वाली मुनज्जम वारदातों ने सन 1980 के दशक की दहशतगर्दी की याद ताजा कर दी है। जब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का संताप पड़ोसी सूबे पंजाब के साथ भारतीय सेना को भी झेलना पड़ा था। सिखों के मुकद्दस अकाल तख्त परिसर में मजबूत मोर्चाबंदी कर चुके अलगाववादियों से निपटने के लिए जून 1984 में सेना को आपरेशन 'ब्लू स्टार' के तहत सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी थी। परिसर में की गई मजबूत किलेबंदी को ध्वस्त करने में सेना की '10 गाड्र्स' बटालियन के हिमाचली शूरवीर कैप्टन 'जसबीर सिंह रैना' ने अहम भूमिका निभाई थी। खतरनाक मिशन में बुरी तरह जख्मी होकर अपने दोनों पांव गवांने के बावजूद जसबीर सिंह मोर्चें पर डटे रहे। सैन्य मिशन में उत्कृष्ट सैन्य नेतृत्व के लिए जसबीर सिंह रैना को भारत सरकार ने शांतिकाल के सर्वोच्च पदक 'अशोक चक्र' से सरफराज किया था। आपरेशन ब्लू स्टार की कार्रवाई में सेना के 83 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, जिनमें 'प्रथम पैरा स्पेशल फोर्स' के सत्रह कमांडो भी बलिदान हुए थे। नायक प्रकाश चंद, जगदीश चंद व दर्शन सिंह तीनों बलिदानी कमांडो का संबंध भी हिमाचल से था। प्रथम पैरा के मेजर प्रकाश चंद कटोच 'शौर्य चक्र' ने मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सन् 1971 की जंग में पूर्वी पाक के महाज पर 'मुक्तिवाहिनी' को प्रशिक्षण देकर पाक सेना को शिकस्त-ए-फाश देने में सिख जरनैल शाबेग सिंह ने अहम किरदार अदा किया था। पाकिस्तान को तकसीम करके नए मुल्क बांग्लादेश के निर्माण में बेहतरीन सैन्य नेतृत्व के लिए भारत के राष्ट्रपति ने शाबेग सिंह को 'परम विशिष्ट सेवा मेडल' से नवाजा था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में गढ़वाल राइफल्स व सन् 1965 की जंग में गोरखा राइफल्स का नेतृत्व करने वाले शाबेग सिंह सेवानिवृत्ति के बाद मजहबी कट्टरपंथ का शिकार होकर अलगाववादियों से जा मिले। अफसोस कश्मीर युद्ध में 'प्रथम पैरा' का हिस्सा रहे अजीम जरनैल आपरेशन ब्लू स्टार की सैन्य कार्रवाई में अपनी ही सेना का शिकार बन गए थे। भावार्थ यह है कि आतंकवाद ने कई घरों के चश्मो-चिराग बुझा दिए हैं। दहशतगर्दी जैसी खौफनाक स्थिति से निपटने में सियासी निजाम व राज्यों की सुरक्षा एजेंसियां नाकाम रही हैं। आतंकवाद जैसी सूरत-ए-हाल से निपटने का विकल्प केवल सेना बनी है। युद्धों व आतंक विरोधी अभियानों में शहीद हुए देश के सैनिकों की वीर वधुओं की बड़ी संख्या तस्दीक करती है कि सियासत के गलत फैसलों का खामियाजा सैन्य परिवार भुगत रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पाक परस्त आतंक से 'राष्ट्रीय राइफल्स' के जवान निपट रहे हैं।

कुछ अलग

स्क्रैच अच्छे हैं...

कुछ स्क्रैच ऐसे होते हैं जिन्हें बुरी नजर से नहीं देख सकते। लोगबाग अपने वाहनों में जबरिया स्क्रैच लगा लेते हैं ताकि नजर न लगे, लेकिन जिसे लगनी है, उसे चुन कर लग जाती है। कुछ लोग तो अपने शरीर और विचारों पर आए स्क्रैच की भी परवाह नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सडक़ से सदन तक इन्हें खोजते रहते हैं। हर चुनाव के प्रचार में स्क्रैच काम आते हैं, लेकिन दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद सबसे अधिक घायल स्क्रैच ही दिखाई दिए। बावजूद इसके राजनीति में हमेशा कुछ स्क्रैच अच्छे होते हैं। जीती हुई पार्टियों के सामने विपक्ष के स्क्रैच अच्छे व वफादार होते हैं। दरअसल सफल नेता होना स्क्रैच फ्री होना है। हम नागरिक वर्षों से सियासी स्क्रैच देख रहे हैं, लेकिन वे नहीं देखते जिन्हें जनता देख रही है। यह देखने-देखने में अंतर है। किसी ने गंगा को हरिद्वार में देखा, किसी ने प्रयागराज में और किसी ने दोनों ही जगह सरकार के रुतबे में अपने विश्वास को देखा। वैसे स्क्रैच फ्री दृष्टि के लिए विश्वास परम उपाय है। एक बार विश्वास करो कि हम भारतीय पूरे विश्व की सबसे अव्वल नस्ल हैं, हम सारे संसार को गंदगी से भरा पाएंगे। हमारे विश्वास की कई आंखें हैं और इसीलिए बदल-बदल कर देखते हैं। आंखों की परख डाक्टर भी क्या करेंगे, जिस तरह शायरों ने की या आज के नेता करते हैं। वे हमारी आंखों के सामने ऐसा निरीक्षण कर देते हैं कि हमें सिर्फ सामने विश्वास ही विश्वास नजर आता है। हमें विश्वास था, इसलिए आंखों ने हमेशा दिल्ली पर विश्वास किया। खुद पर विश्वास करना दिल्ली चुनाव सिखा गया। यही विश्वास कांग्रेस को केजरीवाल की हार में दिखा तो सारे जन इकट्ठे हो गए। वहां खुशी इस बात की थी कि आम आदमी पार्टी की गाड़ी पर सबसे अधिक स्क्रैच थे। उनके स्क्रैच इन्हें अच्छे लगे, वरना विधानसभा के सदन में तो यह पार्टी न पहले देख पाई और न ही अब देखने की हैसियत रखती है। हैसियत तो सबसे कमजोर मध्यम वर्ग की है। सारे देश के स्क्रैच इसी वर्ग को दर्द देते हैं। मिडल क्लास की पढ़ाई, डिग्री और रोजगार पर चस्पां स्क्रैच दिखते नहीं, सालते हैं। इसलिए जिन्होंने आईटी पढ़ा, अब उन्हें कम्प्यूटर के स्क्रैच दर्द देते हैं। दूसरी ओर सरकारी कर्मचारी तो एनपीएस से लेकर यूपीएस तक के स्क्रैच खोज लाए। सरकारी कर्मचारी इसीलिए अपनी कुर्सी पर न ज्यादा वजन डालता और न ही बैठता ताकि कहीं सेवा में कोई स्क्रैच न उभर आए। अब तो सरकारी डाक्टर भी मरीजों को निजी अस्पतालों में भेज कर सरकार के अस्पतालों को स्क्रैच फ्री बनाने लगे हैं। हमें भारत को स्क्रैच फ्री बनाना है, इसलिए अब इतिहास से खोज रहे हैं। महात्मा गांधी के चरखे, अंबेडकर के दफ्तर और नेहरू के कद में वे स्क्रैच खोज लाए हैं। इससे इतिहास के कई नायक अब गायब होने लगे और अब इसका सामाजिक अर्थ यह कि लोग अब अपने पूर्वजों का नाम भी छुपाने लगे हैं, ताकि कहीं कोई उनमें से जाति और धर्म के स्क्रैच न खोज पाए। उस दिन राहुल घबरा गए। किसी ने कहा, 'आपकी भारत यात्रा से सडक़ों पर स्क्रैच उभर आए हैं।' जवाब था, 'नहीं भाई, वहां तो पहले से गड्ढे थे। ये गड्ढों के स्क्रैच कहां दिखाई देते। यह तो गलत इल्जाम है। मैं तो अपनी पार्टी के स्क्रैच भी नहीं देख पाया, तो मेरे कदमों के नीचे खोजने की जरूरत नहीं।' उस दिन पहली बार राहुल सोचने को मजबूर हुए, 'आखिर कितने स्क्रैच इकट्ठे करने पड़ते हैं राजनीति में सफल होने के लिए।' उस दिन से राहुल अपनी ही जमीन पर चलते हुए स्क्रैच से डरने लगे, लेकिन विरोधी गठबंधन ने मिलजुल कर अलग चुनाव चिन्ह 'स्क्रैच' ले लिया।

देश दुनीया से

जंगलों पर छाया इंसानों का आतंक: एक अनदेखा संकट

हाल ही में एक अखबार की प्रमुख हेडलाइन पढ़ी—"शहर में बंदरों और कुत्तों का आतंक"। यह वाक्य महज एक खबर नहीं, बल्कि हमारे सोचने के तरीके का प्रतिबिंब था। हमने जानवरों के शहर में आने को "आतंक" करार दिया, लेकिन कभी यह सवाल नहीं पूछा कि वो शहर में आए ही क्यों? जब कोई बंदर किसी कॉलोनी की छत पर उछलता है, या कोई कुत्ता कूड़े के ढेर में भोजन तलाशता है, तो वह कोई स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं होती। यह उस संकट का संकेत होता है जिसे हम—मनुष्य—ने स्वयं गढ़ा है। जंगल, जो कभी इन जीवों का घर थे, अब रियल एस्टेट की परियोजनाओं, खनन कार्यों, सड़कों और डैमों की बलि चढ़ चुके हैं। आज अगर कोई सच में आतंक फैला रहा है, तो वह है इंसानी लालच और विकास का अंधा मॉडल। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जहाँ जैव विविधता की अद्भुत संपदा है। लेकिन यही भारत आज अपने ही जंगलों को खा रहा है। 2021 की Forest Survey of India रिपोर्ट बताती है कि भारत ने पिछले चार वर्षों में 1,100 वर्ग किलोमीटर से अधिक वनक्षेत्र खो दिया है। हरियाणा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा जैसे राज्यों में यह गिरावट विशेष रूप से चिंताजनक रही है। वन कटान केवल पेड़ों का नुकसान नहीं है। यह पूरी एक पारिस्थितिकी व्यवस्था का ध्वंस है। जब हम पेड़ काटते हैं, हम न सिर्फ ऑक्सीजन के स्रोत मिटाते हैं, बल्कि हजारों पशु-पक्षियों के घर उजाड़ देते हैं। यही कारण है कि आज हमें गाँवों और शहरों के आसपास बाघ, हाथी, भालू और यहाँ तक कि तेंदुए भी दिखने लगे हैं। बंदरों का शहरों में आना आज एक आम दृश्य बन गया है। दिल्ली, वाराणसी, जयपुर, और देहरादून जैसे शहरों में बंदरों की आबादी तेज़ी से बढ़ी है। कारण स्पष्ट हैं—कम होती हरियाली, अधिक होता कूड़ा, और बिगड़ता पारिस्थितिक संतुलन। इसी तरह, आवारा कुत्तों की संख्या भी शहरों में नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। World Health Organization के अनुसार भारत में लगभग 3.5 करोड़ आवारा कुत्ते हैं, और हर साल हजारों लोग कुत्तों के काटने के शिकार होते हैं। मगर यह समस्या केवल स्वास्थ्य या सुरक्षा की नहीं है; यह समस्या हमारे कुप्रबंधन और लापरवाह विकास की है। हमने कूड़ा फेंकने के तरीकों को सुधारा नहीं, सार्वजनिक पशु-नियंत्रण कार्यक्रमों को प्राथमिकता नहीं दी, और अब जब जानवर हमारी बस्तियों में दिखते हैं, तो उन्हें "संकट" कह कर खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हैं। जब कोई अखबार लिखता है कि "बंदरों का आतंक", तो वह केवल सूचना नहीं दे रहा होता, बल्कि एक धारणा गढ़ रहा होता है। यह धारणा कि जानवर आक्रमणकारी हैं, और हम पीड़ित। मीडिया की यही भाषा यह छिपा लेती है कि असल में हम ही उनके घरों में घुसे थे, उनकी ज़मीन छीनी, और अब जब वो अपनी जगह पाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें दोषी ठहराते हैं। यह भाषा केवल संवेदनहीन नहीं, बल्कि खतरनाक भी है, क्योंकि इससे संरक्षण के प्रति समाज की समझ और सहानुभूति दोनों कमजोर पड़ती हैं।

एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर साल औसतन 100 से अधिक लोग हाथियों के हमलों में मारे जाते हैं, और दर्जनों बाघ-मानव संघर्ष की घटनाएँ सामने आती हैं। मगर इन घटनाओं के पीछे की सच्चाई यह है कि वन्यजीवों का घर सिकुड़ता जा रहा है। जंगलों में भोजन और पानी की कमी उन्हें मानव बस्तियों की ओर खींचती है। कभी-कभी वे रास्ता भटक जाते हैं, तो कभी उन्हें मजबूरी में खेतों और घरों में घुसना पड़ता है। यह संघर्ष उनके लिए भी घातक है—हर साल सैकड़ों जानवर इंसानी जवाबी हिंसा में मारे जाते हैं। भारत में Wildlife Protection Act 1972 और Forest Conservation Act 1980 जैसे सशक्त कानून हैं, लेकिन उनके लागू करने में अनेक समस्याएँ हैं। वन विभाग अक्सर संसाधनों और जनबल की कमी से जूझता है। इसके अलावा, जब विकास परियोजनाओं और वन्यजीव संरक्षण में टकराव होता है, तो अक्सर विकास को तरजीह दी जाती है, भले ही उसके दीर्घकालिक परिणाम विनाशकारी हों। इस संकट से उबरने के लिए केवल नीतियाँ नहीं, बल्कि सोच का परिवर्तन ज़रूरी है। कुछ संभावित उपाय इस प्रकार हैं: शहरी नियोजन में हरित क्षेत्र सुनिश्चित किया जाए — पार्क, बाग़-बगिचे, और वृक्षारोपण को केवल सजावटी पहलू नहीं, बल्कि पारिस्थितिकी के हिस्से के रूप में देखा जाए। वन्यजीव गलियारे (wildlife corridors) विकसित किए जाएँ — जिससे जानवरों को सुरक्षित आवागमन का रास्ता मिले। कचरा प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाए — ताकि जानवर शहरी कूड़े पर निर्भर न हों। मीडिया और शिक्षा में संवेदनशीलता लाई जाए — जानवरों को 'आतंकवादी' बताने के बजाय उनके संघर्ष को समझने और सहानुभूति की भाषा अपनाई जाए। स्थानीय समुदायों को शामिल किया जाए — उन्हें संरक्षण के साझेदार बनाना होगा, विरोधी नहीं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि यह धरती केवल हमारी नहीं है। जंगलों, नदियों, पहाड़ों, और समंदरों के साथ-साथ हर जीव-जंतु का इस पर उतना ही अधिकार है जितना हमारा। जब हम शहरों का विस्तार करते हैं, जब हम मॉल और एक्सप्रेसवे बनाते हैं, तब हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी न किसी की ज़मीन छीनी जा रही है—कभी किसी हिरन की, कभी किसी हाथी की। हम अगर प्रकृति से लड़ते रहेंगे, तो अंततः हार हमारी ही होगी—क्योंकि प्रकृति को हराया नहीं जा सकता, बस अस्थायी रूप से दबाया जा सकता है। "बंदरों का आतंक" एक समाचार की हेडलाइन हो सकती है, लेकिन असल हेडलाइन यह होनी चाहिए थी—"जंगलों पर इंसानों का आतंक"। इस सच्चाई को स्वीकार करना कठिन है, लेकिन जरूरी है। अगर हम वास्तव में एक संतुलित, सुरक्षित और संवेदनशील समाज की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो हमें प्रकृति से नहीं, अपने अहंकार से संघर्ष करना होगा।

आप का नजरीया

राम पर इतना तनाव क्यों?

हम आश्चर्य में हैं और अपनी ही चेतना से सवाल कर रहे हैं। हम राम नवमी सहज और सौहार्द के साथ क्यों नहीं मना सकते? राम नवमी की शोभा-यात्रा और अन्य आयोजनों के लिए उच्च न्यायालय से अनुमति लेने की नौबत क्यों आती है? पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार राम नवमी पर रोड़े क्यों बिछाती रही हैं? ममता भी हिंदू हैं। राम उनके भी हैं। राम पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक प्राणी के हैं। राम अवतरित पुरुष हैं। ममता बनर्जी मां काली और दुर्गा की तो पूजा करती रही हैं। फिर 'जय श्रीराम' का उद्घोष उन्हें गाली-सा क्यों लगता है और वह अपना संयम खोने लगती हैं? साल-दर-साल राम नवमी के आयोजनों पर सरकारी प्रतिबंध क्यों लगाए जाते रहे हैं? संविधान ने 'धार्मिक स्वतंत्रता' का मौलिक अधिकार हिंदुओं, राम-भक्तों, को भी प्रदान किया है। क्या राम की शोभा-यात्रा आयोजित करना और आस्थाओं के साथ त्योहार मनाना भी गुनाह या पाप है? ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा प्रत्येक नागरिक की जन-प्रतिनिधि हैं, संवैधानिक अभिभावक हैं। सरकार के नाते यह उनका दायित्व है कि औसत नागरिक उल्लास और उमंग के साथ अपने पर्व मना सके, लेकिन बंगाल ही नहीं, बिहार, उप्र, महाराष्ट्र और झारखंड सरीखे राज्यों में भी, राम नवमी के दिन, राम के नाम पर ही, एक खौफनाक तनाव पसरा रहा। वहां सुरक्षा की पहरेदारियां बिठाई गईं। उप्र के तो 42 जिलों और पश्चिम बंगाल के 10 संवेदनशील जिलों में 'हाई अलर्ट' घोषित करना पड़ा। उप्र में संभल क्षेत्र 'सांप्रदायिकता का कुरुक्षेत्र' क्यों बन गया है? बंगाल के हावड़ा इलाके और उप्र के कई शहरों में सुरक्षा बलों, पुलिस को 'फ्लैग मार्च' निकालने पड़े, चप्पे-चप्पे पर पहरे और घेराबंदियां बिठा दी गईं। ड्रोन चलाए गए, सीसीटीवी से भी निगरानी करनी पड़ी। यह 'राम नवमी' त्योहार का दिन था अथवा किसी आतंकी हमले की आशंका थी? ये सुरक्षा-घेरे सहज नहीं लगे। आखिर इतने व्यापक तनाव के कारण क्या थे? क्या देश में धार्मिक सहिष्णुता समाप्त हो चुकी है? होली बनाम अलविदा जुमा, नवरात्रि बनाम ईद की नमाज सरीखे सांप्रदायिक टकराव के हालात क्यों बन रहे हैं? क्या सरकारें ही नाकाम हैं? या सरकारें ही दंगेनुमा स्थितियां पैदा करवा रही हैं? आखिर देश में यह कब तक चलता रहेगा? बंगाल में ममता सरकार बीते सालों में भी राम नवमी, दुर्गा पूजा, हनुमान जयंती सरीखे हिंदुओं के त्योहारों पर वर्जनाएं थोपती रही हैं। अंततः अदालत की शरण में जाना पड़ता है। ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार दंगे भडक़ा रही है। इनसान को इनसान से लड़वा रही है। इसकी प्रतिक्रिया में बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भाजपा एवं हिंदू कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि सभी अपनी गाड़ी या बाइक पर भगवा झंडा लगा कर पूरा दिन शहर में घूमते रहें। दुकानों पर भी अपनी पहचान का झंडा लगाया जाए। ऐसे बयान उत्तेजक साबित हो सकते हैं। दावा किया गया कि हजारों शोभा-यात्राएं निकाली जाएंगी और करीब 5000 जगहों पर श्रीराम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। प्रशासन और अदालत के निर्देश हैं कि शोभा-यात्रा में कोई भी हथियार लेकर शामिल नहीं होगा। क्या राम नवमी हथियार लेकर मनाई जाती रही है? दरअसल ममता और भाजपा दोनों ही वोट बैंक को ध्रुवीकृत करने और अंततः चुनाव जीतने का खेल कर रहे हैं। अनुमान है कि शोभा-यात्राओं में करीब 1.5 करोड़ हिंदुओं ने शिरकत की। ये आयोजन प्रतीकात्मक भी हो सकते थे।

न्याय के तराजू पर भी वक्फ बिल जब तुलेगा तो सही दिशा पकड़ेगा : मंत्री अर्जुन राम मेघवाल

बीकानेर (हिंस)। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में वक्फ बिल को लेकर विपक्षी दलों के साथ राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। बीकानेर दौरे पर आए मंत्री मेघवाल ने कहा कि संसद में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ, यह एक ऐतिहासिक कदम है नरेंद्र मोदी सरकार का। उन्होंने कहा कि इस प्रशासनिक विषय को धार्मिक स्वतंत्रता, संविधान का उल्लंघन यह कहकर के पूरे समाज में कुछ नेता भ्रम फैला रहे हैं। राहुल गांधी स्वयं संसद में थे लेकिन उन्होंने भाग नहीं लिया। जबकि राहुल गांधी को भाग लेकर अपनी बात करनी चाहिए थी। उनको भी पता है कि धार्मिक भावनाओं में हस्तक्षेप नहीं है, वो कहते हैं की संसद को अधिकार

नहीं है। तो वो बताए कि आपने 1954, 1995 व 2013 में कैसे अमेंडमेंट किया। इसी संसद से किया था तो मोदीजी ने भी संसद से अमेंडमेंट किया है क्या दिक्कत है इसमें। वहीं उन्होंने कांग्रेस संसद इमरान मसूद के बिल को लेकर कोर्ट में जाने की बात को लेकर कहा कि कोर्ट में जाने का उनको अधिकार है, ज्यूडिशल रिव्यू के तराजू पर यह बिल निश्चित रूप से तोला जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें कहीं भी संविधान का उल्लंघन नहीं है, संविधान के अनुच्छेद का कोई उलझन नहीं है और संसद को पूरी ताकत है अमेंडमेंट करने की, उसके तहत हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि न्याय के तराजू पर भी यह बिल जब तुलेगा तो सही दिशा पकड़ेगा।

नहर में जल प्रदूषण रोकने के लिए पंजाब और केंद्र सरकार को पत्र लिखे : मंत्री रावत

हनुमानगढ़ (हिंस)। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत सोमवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। लखूवाली हैड, घग्घर नदी और डायवर्जन कैनाल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की 8 अप्रैल को जिले में प्रस्तावित यात्रा की तैयारियों को लेकर जनप्रतिनिधियों, जिला कलेक्टर काना राम और विभागीय अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री व जिला प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा, विधायक गणेश राज बंसल, पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया, धर्मेन्द्र मोची, जनप्रतिनिधि प्रमोद डेलू, देवेंद्र पारीक, अमित सहू, सम्भागीय आयुक्त रविकुमार सुरपुर, जिला कलेक्टर काना राम, पुलिस अधीक्षक अरशद अली, मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव (पश्चिम) अमरजीत सिंह, मुख्य अभियंता (उत्तर) प्रदीप रुस्तगी साथ उपस्थित रहे।

बटाला में पुलिस थाना के पास विस्फोट खालिस्तानी समर्थक संगठन ने किया हमले का दावा

चंडीगढ़(हिंस)। गुरदासपुर जिले के बटाला के अंतर्गत किला लाल सिंह पुलिस स्टेशन पर सोमवार अल सुबह करीब तीन बजे एक ग्रेनेड विस्फोट होने से हड़कंप मच गया। इसके बाद खालिस्तानी समर्थक संगठन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर पुलिस थाना पर ग्रेनेड से हमला करने का दावा किया है। पुलिस अभी कुछ भी बताने से बच रही है। सोमवार सुबह करीब तीन बजे बटाला के अंतर्गत किला लाल सिंह पुलिस स्टेशन के पास विस्फोट हुआ। किला लाल सिंह पुलिस स्टेशन के पास रहने वाले लोगों ने बताया कि रात 3 बजे जोरदार धमाके की आवाज आई थी। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस का दावा है कि अभी मामले की जांच की जा रही है। कोई भी अधिकारी अधिकारिक रूप से कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर

बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने लिखा कि हैप्पी पासियां ने इसकी जिम्मेदारी ली है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में हुए एनकाउंटर का बदला लेने के लिए रॉकेट लांचर से पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया। खालिस्तानी संगठन की ओर से की गई पोस्ट में लिखा है कि बटाला के निकट किला लाल सिंह गांव के पुलिस स्टेशन पर कल रात रॉकेट लांचर से हमला हुआ। इसकी जिम्मेदारी मैं हैप्पी पासियां, मन्नू अगवान और गोपी नवांशहरिया लेता हूं। यह यूपी पीलीभीत और बटाला में पुलिस के एनकाउंटरों का बदला था। अपनी पोस्ट में लिखा कि इस एनकाउंटर की कार्रवाई में शामिल जिन पुलिस अधिकारियों व पुलिसकर्मियों के नाम हैं, उन्हें उनके किए की सजा दी जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये हमले तब तक जारी रहेंगे, जब तक यह पुलिस सिख समुदाय पर अत्याचार करना बंद नहीं करेगी।

राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र में ऊंट पालकों के कल्याणार्थ करेंगे और अधिक बेहतर काम : पूनिया

बीकानेर (हिंस)। राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र (एनआरसीसी) के नए निदेशक के रूप में डॉ. अनिल कुमार पूनिया ने सोमवार को अपना कार्यभार संभाला। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व डॉ. पूनिया, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल में प्रधान वैज्ञानिक (डेरी सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रभाग) के रूप में कार्यरत थे। इस उपलक्ष्य पर आयोजित अभिनन्दन समारोह में डॉ. अनिल कुमार पूनिया, निदेशक, एनआरसीसी ने केंद्र परिवार को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सभी अनुसंधान संस्थानों की स्थापना के पीछे मूल ध्येय, किसानों के कल्याणार्थ कार्य करना है। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए हमारा संस्थान, उष्ट्र प्रजाति के संरक्षण व विकास की दिशा में अनुसंधानिक प्रयास जारी रखेगा तथा ऊंट पालकों के कल्याणार्थ जमीनी स्तर पर और अधिक तत्परता तथा बेहतर ढंग से कार्य करेगा ताकि परिवर्तित परिदृश्य में उष्ट्र पालन व्यवसाय को लाभदायक बनाया जा सकें। डॉ. पूनिया ने एनआरसीसी संस्थान के सभी पूर्व निदेशकों द्वारा संस्थान की प्रगति के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्यों की सराहना की। उन्होंने सहज, सरल लहजे में अपनी बात रखते हुए अनुसंधान की ताजा खबरें (ब्रेकिंग न्यूज), टीम वर्क के रूप में पूर्ण मनोयोग से कार्य करने, विनम्रता युक्त व्यवहार रखने, तकनीक का भरपूर इस्तेमाल करने तथा खासकर महिलाओं को खुले मन से अपने कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने को प्रोत्साहित किया।

पूरे देश में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में उत्तर प्रदेश को मिला अग्रणी स्थान

लखनऊ (हिंस)। वित्त विभाग से जारी आंकड़ों में उत्तर प्रदेश ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) में पूरे देश में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। 2017-18 में राज्य में 122.84 करोड़ डिजिटल ट्रांजेक्शन हुए थे, वहीं 2024-25 में दिसम्बर तक आंकड़ा 1024.41 करोड़ तक पहुंच गया है। डिजिटल लेनदेन में उत्तर प्रदेश के प्रथम स्थान पर पहुंचने में ज्यादातर ट्रांजेक्शन यूपीआई से हुए हैं। प्रदेश के वित्त विभाग ने इस कामयाबी पर विज्ञप्ति जारी कर बताया कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने डिजिटल क्रांति को हर घर तक पहुंचाने का सपना सच कर दिखाया है। डिजिटल बैंकिंग को आसान बनाने के साथ-साथ गांवों तक हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा पहुंचाई गई हैं। लोगों को इसके फायदे समझाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। वर्तमान आंकड़े को देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 20, 416 बैंक शाखाएं हैं जिससे चार लाख 932 बैंक मित्र और बीसी सखी भी जुड़े हैं। करीब 18, 747 एटीएम संचालित हैं और चार लाख 40 हजार 95 बैंकिंग केंद्र काम कर रहे हैं। ये सुविधाएं शहरों से लेकर दूरदराज के गांवों तक लोगों की मदद कर रही हैं।

मोगा सेक्स स्कैंडल मामले में दोषी चार पूर्व पुलिस अधिकारियों को पांच-पांच साल की सजा

चंडीगढ़ (हिंस)। सीबीआई की विशेष अदालत ने पंजाब के मोगा में 18 साल पहले हुए सेक्स स्कैंडल मामले में चार पूर्व पुलिस अधिकारियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। इस मामले में एक पुलिस अधिकारी को तीन साल की अतिरिक्त सजा के साथ कुल आठ साल की सजा सुनाई गई है। सोमवार को न्यायाधीश राकेश कुमार गुप्ता द्वारा सुनाई गई सजा के अनुसार सभी दोषियों पर दो-दो लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने इस मामले में मोगा जिले के तत्कालीन एसएसपी दविंदर सिंह गरचा, पूर्व एसपी हेडक्वार्टर मोगा परमदीप सिंह संधू, पूर्व एसएचओ थाना सिटी मोगा रमन कुमार और पुलिस स्टेशन मोगा के तत्कालीन एसएचओ इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह को सजा सुनाई है। यह मामला राज्य में वर्ष 2007 में सामने आया था। मोगा के थाना सिटी ने जगराओं के एक गांव की लड़की की शिकायत पर गैंगरेप का मामला दर्ज किया था। इसके बाद पीड़ित लड़की के बयान दर्ज किए। इसमें उसने करीब 50 अज्ञात लोगों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस अधिकारियों ने इस केस की जांच में गड़बड़ी की। केस में कई व्यापारियों और राजनेताओं के नाम शामिल करने शुरू कर दिए। इसी दौरान एक नेता ने पुलिस के पैसे मांगने की ऑडियो रिकॉर्ड कर ली। इससे यह मामला सुर्खियों में आ गया। 12 नवंबर 2007 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले का खुद ही संज्ञान लिया। साथ ही पुलिस से इस मामले की रिपोर्ट मांगी। इसके बाद सारे केस की जांच करने के बाद हाई कोर्ट ने मामला सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई कोर्ट में लंबी जिरह के बाद 29 मार्च को उक्त सभी पुलिस अधिकारियों को दोषी करार दिया गया था। सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाया गया। शिकायकर्ता रनजीत सिंह ने कहा कि फैसला बहुत बढ़िया आया है। उन्होंने कहा कि वह फैसले से संतुष्ट हैं। सीबीआई कोर्ट ने देविंदर सिंह गरचा और पीएस संधू को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1), 13(2) के तहत दोषी करार दिया है। रमन कुमार को इस केस में तीन साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। जिसके चलते उन्हें आठ साल की सजा भुगतनी होगी।

जन समस्याओं के समाधान में ढीलाई न बरतें अधिकारी : डीसी

रोहतक (हिंस)। उपायुक्त धीरेंद्र खड़टा ने प्रशासनिक अधिकारियों से समाधान शिविर में आने वाले लोगों को संतुष्ट करके ही घर वापस भेजने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को उपायुक्त लघु सचिवालय के सभागार में आए आमजन की समस्याओं का निपटान कर रहे थे। डीसी ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार का उद्देश्य लोगों के जीवन को आसान बनाना है, ताकि उन्हें अपने काम करवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं समाधान शिविरों की मॉनीटरिंग कर रहे हैं। इसलिए कोई भी अधिकारी जन समस्याओं के समाधान के मामले में कोताही अथवा ढिलाई ने बर्तें। उपायुक्त धीरेंद्र खड़टा ने कहा कि राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार सप्ताह में दो दिन सोमवार व वीरवार को समाधान शिवरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि शुक्रवार को समाधान शिवर में आने वाली शिकायतों के निपटान की समीक्षा भी की जाती है। धीरेंद्र खड़टा ने कहा कि विभिन्न विभागों से संबंधित जन शिकायतों का एक ही स्थान पर समाधान करने के लिए समाधान शिविर जिला मुख्यालय व उपमंडल स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं।

नए कानून से किसानों व दुकानदारों को भी फायदा : लखविंद्र सिंह

सिरसा (हिंस)। भारतीय किसान एकता के प्रधान लखविंद्र सिंह ने कहा कि दुकानदार बीज विक्रेताओं के बहकावे में न आएं। नए कानून से किसानों के साथ-साथ सही काम करने वाले दुकानदारों को भी फायदा होगा। लखविंद्र सिंह ने सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा में चुनाव से पहले बीजेपी ने किसानों से वायदा किया था की सीड, पेस्टीसाइड व फर्टिलाइजर का गलत काम करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानून लेकर आएंगे। हमारी इस विषय में सरकार व उच्चाधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें हुई। पिछले 11 सालों से हरियाणा की सत्ता में स्थापित बीजेपी ने किसानों के हक में पहली बार अच्छा काम किया है। हालांकि हम इस कानून को और सख्त बनाने के हक में हैं, जिससे किसान व किसानी की हो रही बर्बादी को रोका

जा सके। इस संशोधन से किसानों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात तो ये है कि पेस्टीसाइड सीड व फर्टिलाइजर माफिया इतना हावी हो चुका है कि वह सरेआम सरकार को चेतावनी दे रहा है कि हम गलत काम भी करेंगे और अपने खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होने देंगे। लखविंद्र सिंह ने सरकार मांग की है कि सभी सरकारी व सहकारी बिक्री केंद्रों पर बीज, खाद व पेस्टीसाइड की बिक्री सुनिश्चित करवाई जाए, ताकि किसान को किसी प्रकार की दिक्कत न आए।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष खुद पार्टी को कर रहे पंक्चर : डोटासरा

उदयपुर (हिंस)। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोमवार को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राठौड़ खुद अपनी पार्टी को पंक्चर करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के पास न तो कोई स्पष्ट विजन है और न ही जनहित के मुद्दों को लेकर कोई गंभीरता। उदयपुर के डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने कहा, छह से आठ महीने में राठौड़ का कोई विजन नहीं दिखा, बस छतों पर भाजपा का झंडा फहरा रहे हैं। ये केवल नौटंकी करने वाले लोग हैं। डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे केवल दिल्ली से आने वाली पर्ची पढ़ने तक सीमित हैं। डोटासरा बोले, राज्य में ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह हावी है, मुख्यमंत्री की कोई निर्णायक भूमिका नहीं दिखती।

सरकार का संकल्प, किसी के साथ नहीं होगा अन्याय : मुख्यमंत्री

अफसरों को दिए निर्देश, त्वरित व संतुष्टिपरक हो समस्याओं का समाधान

गोरखपुर (हिंस)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन, सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में करीब 300 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने समस्या लेकर आए लोगों से आत्मीयता से संवाद करते हुए कि किसी को भी घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर सुनिश्चित कार्रवाई करते हुए समस्या का समाधान कराया जाएगा। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लोगों की समस्याओं का निस्तारण उनकी सरकार की विशेष प्राथमिकता है। पीड़ितों की समस्याओं को गंभीरता और संवेदनशीलता से लेते हुए उनका समाधान त्वरित और संतुष्टिपरक तरीके से कराना सुनिश्चित कराएं। जनता दर्शन के दौरान सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर परिसर में महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद गए और एक-एक कर उनकी समस्याओं को सुना। सबको आश्वस्त किया कि किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सबकी समस्या का समाधान हरहाल में किया जाएगा। सरकार का संकल्प है कि किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने दिया

जाएगा। जनता दर्शन में कुछ महिलाएं जमीन से जुड़े विवादों में प्रार्थना पत्र लेकर पहुंची थीं। कुछ की शिकायत थी कि दबंग उनकी जमीनों पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इन शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जमीन कब्जाने में पेशेवर प्रवृत्ति वालों को भू माफिया के रूप में चिन्हित कर सख्ती की जाए। किसी भी गरीब की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करें जो नजीर बने। जमीनी विवादों का समाधान तत्परतापूर्वक इस तरह होना चाहिए जिससे पीड़ित व्यक्ति संतुष्ट दिखे। जनता दर्शन में प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को हस्तगत करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि हर समस्या का निस्तारण त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिप्रद होना चाहिए। पारिवारिक रिश्तों को लेकर विवाद संबंधी शिकायतों पर सीएम ने अफसरों से कहा कि सबसे पहले इसमें सभी पक्षों को एकसाथ बैठाकर संवाद करने की जरूरत है। जनता दर्शन में कुछ महिलाएं अपने बच्चों को लेकर आई थीं। मुख्यमंत्री ने बच्चों को दुलारकर आशीर्वाद दिया। उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा और चॉकलेट गिफ्ट कर उन्हें खूब पढ़ने को प्रेरित किया। गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोमवार सुबह की दिनचर्या परंपरागत रही। प्रात: काल गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन करने तथा अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की समाधि स्थल पर मत्था टेकने के बाद वह मंदिर परिसर के भ्रमण पर निकले। गोशाला जाकर मुख्यमंत्री ने गोसेवा की। गोशाला के समीप एक मोर को रोटी और केला खिलाकर उस पर अपना स्नेह लुटाया। मंदिर परिसर का भ्रमण करने के दौरान सीएम योगी की नजर अपने परिजनों संग आए बच्चों पर पड़ी तो उन्होंने बच्चों को पास बुला लिया। उनसे हंसी ठिठोली करके खूब प्यार-दुलार किया और चॉकलेट गिफ्ट की। एक नन्हा बच्चा चॉकलेट का रैपर नहीं खोल पा रहा तो मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से रैपर हटाकर उसे खाने को दिया।

1051 कन्याओं का पूजन, नौ देवियों की सजीव झांकी और छप्पन भोग भी लगाया

बीकानेर (हिंस)। श्री लक्ष्मीनाथ नवयुवक मंडल एवम मां सती माता भक्त मंडल द्वारा भांडाशाह जैन मंदिर में 1051 कन्याओं का पूजन किया गया। लक्ष्मी माता उद्योग मंडल के अध्यक्ष राजेश छंगाणी ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में पंडित पुखराज भादाणी ओर 11 वेदपाठी ब्राह्मणों दुवारा मां दुर्गा का पंचामृत अभिषेक के साथ दुर्गा सप्तशती पाठ सहित पूजन करवाया गया। पूजन कार्यक्रम में अनेक जोड़ों ने पुजन करवाया। वही पंडित राजेंद्र किराडू, दिलीप जोशी, राजेश चुरा, पंडित जुगल किशोर जीओझा, ललित छंगाणी, विधायक जेठानंद व्यास, उद्योगपति रमेश अग्रवाल सहित अनेक समाजसेवी, राजनेता सहित अनेक गणमान्य लोग पहुंचे। वही कार्यक्रम में नौ देवियों की सजीव झांकी और छप्पन भोग भी लगाया गया। कार्यक्रम के दौरान महिला मंडल द्वारा माताजी एवं गणगौर गीतों का गायन किया गया। भजन गायक सुनील तंवर ने माता रानी के भजनों की प्रस्तुति देकर समां बांध दिया। आयोजित कार्यक्रम के अध्यक्ष भैरू रतन ने बताया कि दोनों ही संस्था के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कन्या पूजन के साथ-साथ माता-पिता का भी पूजन किया गया। माता रानी के पूरी सब्जी का भोग लगाया गया।

पांच दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा

अररिया (हिंस)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि कुमार की अदालत ने आठ साल पहले गला दबाकर हत्या करने वाले पांच दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा के साथ 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसले में हत्या के अपराध के साथ ही साक्ष्य छुपाने के मामले में पांच वर्षों के साथ 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने दोनों ही धाराओं में सजा साथ चलाने का आदेश अपने निर्णय में दिया है। मामला अररिया थाना प्राथमिकी कांड संख्या 585/2016 से सबंधित हैं। सजा पाने वाले दोषियों में लालटू उर्फ अरविंद यादव पिता भोला नाथ यादव, अशोक यादव पिता स्वर्गीय तुलसी प्रसाद यादव, अशोक साह पिता परमानंद साह, नरेंद्र कुमार यादव पिता जीतन लाल यादव है। सभी दोषी महलगांव थाना क्षेत्र बागनगर के रहने वाले हैं। वहीं पांचवां दोषी महलगांव थाना क्षेत्र के मलहरिया गांव के बीरेंद्र यादव पिता मोहन लाल यादव हैं। प्राथमिकी कन्हैया यादव पिता मायानन्द यादव के द्वारा दर्ज कराई गई थी। दोषियों ने 6 सितंबर 2016 को दिन के 4 बजे गांव बागनगर महलगांव चौरा शिव मंदिर के निकट एबीसी नहर में आपसी विवाद में कन्हैया यादव के भाई मुरली यादव की गला मरोड़कर हत्या कर दी थी और लाश को नहर के पानी में छुपा दिया था। सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता कृष्ण मोहन सिंह और देव नारायण सेन ने कोर्ट से कम उम्र का हवाला देते हुए कम से कम सजा सुनाए जाने की गुहार लगाई, जबकि सरकार की ओर से लोक अभियोजक लक्ष्मी नारायण यादव और अपर लोक अभियोजक प्रभा कुमारी ने न्यायालय के समक्ष अपनी दलीलें दी। दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोषियों को आजीवन सश्रम कारावासऔर जुर्माने की सजा सुनाई।

आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से भी राहत

जोधपुर (हिंस)। अपने ही गुरुकुल की छात्रा से यौन शोषण के आरोप में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। गुजरात हाईकोर्ट के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट से भी अंतरिम जमानत राहत की अवधि 30 जून तक बढ़ाई गई है। यह राहत उसके स्वास्थ्य को देखते हुए दी गई है। आसाराम के गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए अंतरिम जमानत अवधि को बढ़ाया है। लम्बी बहस के बाद यह फैसला दिया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013 से आसाराम अपने ही गुरुकुल की छात्रा से यौन शोषण के आरोप में जेल में है। उसके बाद कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुना रखी है। वह कई बार गिरते स्वास्थ्य को लेकर में जमानत याचिका लगा चुका है। अभी कुछ दिन पहले ही स्वास्थ्य को लेकर जमानत पर था। अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने के बाद जेल भेजा गया था।

दलित, आदिवासी, पिछड़ा और महिलाओं की लड़ाई हम लड़ेंगे : राहुल गांधी

बिहार में राहुल गांधी ने किया संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित

पटना (हिंस)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश में अगर आप दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़ा और महिला हो तो आप दोयाम दर्जे के हो। हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। वह सोमवार को बिहार की राजधानी पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने बिहार प्रदेश कांग्रेस की टीम को साफ निर्देश दिया है कि आपको बिहार के गरीबों का नेतृत्व करना है। आपको गरीबों व दलितों को आगे बढ़ाना है। हम आपको राजनीति में लाकर बिहार का चेहरा बदलना चाहते हैं। बिहार की भारतीय जनता पार्टी-जनता दल (यूनाइटेड) सरकार अरबपतियों के जरिए राजनीति चल रही है। अंबानी-अडाणी की राजनीति चल रही, उसको हम हराने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि इस देश को राजनीतिक रूप से बिहार ने हमेशा रास्ता दिखाया है। अंग्रेजों के खिलाफ

राजनीतिक बदलाव आया तो बिहार की जनता ने आवाज बुलंद की। हम सबसे जरूरी लक्ष्य संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। पहले प्रधानमंत्री मोदी 400 पार का नारा देते थे तो इंडिया गठबंधन सामने आया। रिजल्ट सबके सामने है। आपने लोकसभा चुनाव में संविधान को बचाने का काम किया। जहां भी मेरी जरूरत होगी, आप मुझे बुलाओ मैं हाजिर हो जाऊंगा। आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई है। इससे पहले राहुल गांधी *पलायन रोको नौकरी दो यात्रा* में शामिल होने के लिए बेगूसराय के सुभाष चौक पर पहुंचे। यहां से राहुल गांधी पैदल ही सुभाष चौक से लेकर हर हर महादेव चौक तक यात्रा में शामिल हुए। हजारों की संख्या में लोग उनके स्वागत में जुटे हुए थे। जगह-जगह राहुल गांधी को फूल बरसा कर उनका स्वागत किया। यह पदयात्रा कन्हैया कुमार के नेतृत्व में की गई थी। राहुल गांधी को देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ उमड़ पड़ी। उल्लेखनीय है कि नमक सत्याग्रह आंदोलन की 95वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें नोनिया समाज के अमर शहीद बुद्धु नोनिया के योगदान के साथ ही शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान पर चर्चा की गई। साथ ही वर्तमान में अति पिछड़ा समाज की दशा और भारतीय संविधान पर बात हुई।

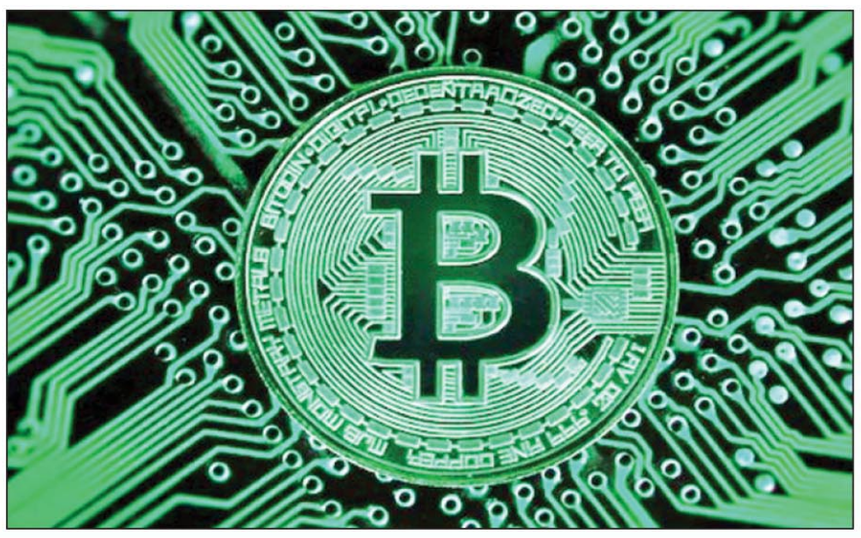

ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से क्रिप्टो मार्केट भी गिरा, 77 हजार डॉलर से भी नीचे आया बिटकॉइन

नई दिल्ली

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के कारण दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में हलचल मचने के साथ ही क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी जबरदस्त गिरावट आ गई है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत लगातार गिरती जा रही है। जनवरी में 1,09,000 डॉलर के स्तर को पार करने वाला बिटकॉइन के कारोबार में 76,753 डॉलर के स्तर तक गिर चुका है।

अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में स्ट्रैटेजिक क्रिप्टो रिजर्व बनाने और क्रिप्टो से जुड़े नियमों में ढील देने की बात कही थी। इसी वजह से चुनाव परिणाम आने के बाद बिटकॉइन की कीमत में जोरदार तेजी दर्ज की गई थी। चुनाव परिणाम आते ही 6 नवंबर, 2024 को इस क्रिप्टो करेंसी ने पहली बार 75 हजार डॉलर के आंकड़े को पार किया था। इसके बाद लगातार तेजी दिखाते हुए ये क्रिप्टो करेंसी 20 जनवरी, 2025 को अपने सर्वोच्च स्तर 1,09,114.88 डॉलर की ऊंचाई पर पहुंच गई। बिटकॉइन में आई इस तेजी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ का राग छेड़ना शुरू कर दिया, जिससे ग्लोबल ट्रेड वॉर शुरू होने की आशंका बन गई। इस वजह से स्टॉक मार्केट की तरह ही क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी दबाव बन गया, जिससे बिटकॉइन की चाल में भी गिरावट आने लगी। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी लागू होने के बाद इस क्रिप्टो करेंसी की चाल में जोरदार गिरावट दर्ज की गई है। बिटकॉइन फिलहाल अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 29 प्रतिशत से अधिक की गिरावट का शिकार हो चुका है। के कारोबार में ये क्रिप्टो करेंसी लुढ़क कर 76,753.35 डॉलर के स्तर तक गिर चुकी है। बिटकॉइन की तरह ही दूसरी प्रमुख क्रिप्टो करेंसीज भी अमेरिका की नई ट्रेड पॉलिसी की वजह से बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं।

न्यूज ब्रीफ

माइक्रोडेटा: एमओएसपीआई का नया अभियान

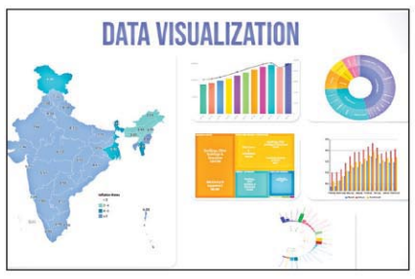

नई दिल्ली। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने विप्लवात्मक प्रौद्योगिकी के साथ नई माइक्रोडेटा मंच की शुरुआत की है। इस मंच का उद्देश्य सार्वजनिक आंकड़ों को सुविधाजनक और दृढ़ ढंग से पहुंचाना है। मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि नया मंच राष्ट्रीय सर्वेक्षणों और आर्थिक जानकारी से एकत्रित व्यापक सांख्यिकीय आंकड़ों के लिए एक केंद्रीकृत भंडार के रूप में काम करेगा। यह मंच पिछले सिस्टम के तकनीकी कड़ीयों को सुधारकर उपयोगकर्ताओं का अनुभव बेहतर बनाएगा। विश्व बैंक के प्रौद्योगिकी दल के सहयोग से, यह प्रणाली नए सुरक्षा मानकों का पालन करने के साथ ही उत्तरदायित्वपूर्ण तंत्र को भी समर्थित करेगी। मंत्रालय ने कृत्रिम मेधा/मशीन लर्निंग का प्रमाण (पीओसी) भी पेश किया है, जो राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के उपयोग को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी की वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। इस नए पहल के माध्यम से, एमओएसपीआई एक सुगम और स्केलेबल ढंचे का इस्तेमाल करके देश में विकास को गति देने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

देश के कई राज्यों में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल, बिहार में बढ़े भाव, ब्रेंट क्रूड का भाव करीब ढाई डॉलर टूटकर 63.33 डॉलर प्रति बैरल हुआ

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से कच्चे तेल की कीमत में वैश्विक बाजार में बड़ी गिरावट देखी गई है। इसका असर घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतों पर भी दिखा और सोमवार को सरकारी तेल कंपनियों ने कई शहरों में तेल के दाम घटा दिए हैं। यूपी, हरियाणा सहित कई राज्यों में सोमवार को तेल सस्ता हुआ है, जबकि बिहार में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में उछाल दिख रहा है। सरकारी तेल कंपनियों के अनुसार, यूपी की राजधानी लखनऊ में पेट्रोल 11 पैसे सस्ता होकर 94.58 रुपये लीटर बिक रहा है. डीजल भी 13 पैसे गिरा और 87.68 रुपये लीटर पहुंच गया है. हरियाणा की राजधानी गुरुग्राम में पेट्रोल 21 पैसे गिरकर 94.96 रुपये और डीजल 20 पैसे टूटकर 87.82 रुपये लीटर हो गया है। बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल 51 पैसे बढ़त के साथ 106.11 रुपये लीटर हो गया तो डीजल 49 पैसे महंगा होकर 92.92 रुपये लीटर बिक रहा है। कच्चे तेल में बड़ी गिरावट दिख रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव करीब ढाई डॉलर टूटकर 63.33 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया है। डब्ल्यूटीआई भी बड़ी गिरावट के साथ 59.81 डॉलर प्रति बैरल हो गया है।

अमेरिका को भारत के निर्यात में उच्च शुल्क से 5.76 अरब डॉलर गिरावट के आसार: जीटीआरआई

नई दिल्ली। अमेरिकी शुल्क में वृद्धि के कारण इस वर्ष समुद्री सामान, सोना, इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रॉनिक जैसे क्षेत्रों से अमेरिका को भारत के माल निर्यात में 5.76 अरब डॉलर की गिरावट आने के आसार हैं। आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनीशिएटिव (जीटीआरआई) ने ऐसा आकलन किया है। यह गिरावट भारत की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान पहुंचाने के लिए भी जिम्मेदार हो सकती है। अमेरिका ने दवा सेमीकंडक्टर, और कुछ ऊर्जा वस्तुओं को छोड़कर भारतीय वस्तुओं पर नौ अप्रैल से 26 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की है। इससे 2025 में भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात में 5.76 अरब अमेरिकी डॉलर या 6.41 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है। इससे प्रमुख उत्पाद समूहों में कमी की संभावना जताई गई है।

आरबीआई की पहली एमपीसी बैठक शुरू रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती संभव

मुंबई

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की वित्त वर्ष 2025-26 में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की पहली समीक्षा बैठक सोमवार को यहां शुरू हो गई। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में आयोजित तीन दिवसीय द्वमासिक यह बैठक 7 से 9 अप्रैल तक चलेगी। आरबीआई गवर्नर 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे इस बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देंगे। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इस बार भी रिजर्व बैंक रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती करेगा।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में तीन दिवसीय द्वमासिक मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा बैठक की शुरुआत हो गई है, जो 9 अप्रैल तक चलेगी। गवर्नर संजय मल्होत्रा 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे इस बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देंगे। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी नीतिगत दर रेपो रेट में 0.25 फीसदी तक की कटौती कर सकता है।

मौद्रिक नीति समिति क्या है

आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं। इनमें से 3 सदस्य रिजर्व बैंक के होते हैं, जबकि बाकी 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। छह सदस्यीय इस समिति को मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मौद्रिक पॉलिसी बनाने के अलावा प्रमुख नीतिगत ब्याज दरें निर्धारित करने का काम सौंपा गया है। ये बैठक आमतौर पर प्रत्येक दो महीने में होती है।

क्या होता है रेपो रेट

रेपो रेट वह नीतिगत ब्याज दर होता है जिस पर भारत के बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) से पैसे उधार लेते हैं। आरबीआई जब इस दर को कम करता है, तो बैंक भी कम ब्याज दरों पर ग्राहकों को लोन दे सकते हैं। इसका मतलब है कि लोन लेने वाले लोगों को कम ब्याज देना होगा। अगर रेपो रेट कम होती है तो होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन पर ब्याज दरें कम हो जाएंगी। इसके साथ ही कारोबारियों के लिए लोन लेना भी आसान हो जाएगा।

वर्तमान में एमपीसी के सदस्य

रिजर्व बैंक के वर्तमान में छह सदस्य हैं। इनमें आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, केंद्रीय बैंक के कार्यकारी निदेशक डॉ. राजीव रंजन, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव, डॉ. नागेश कुमार, डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव, औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के सौगता भट्टाचार्य, अर्थशास्त्री प्रोफेसर राम सिंह, डायरेक्टर, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय हैं।

आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 की आखिरी एमपीसी की समीक्षा बैठक में रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती की थी, जिसे 6.50 फीसदी से घटकर 6.25 फीसदी किया गया था। आरबीआई ने यह कटौती करीब 5 साल के बाद की थी। आरबीआई की मौद्रिक समीक्षा बैठक आमतौर पर हर दो महीने में होती है। इस वित्तीय वर्ष में कुल 6 बैठकें होंगी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं। इनमें से 3 आरबीआई के होते हैं, जबकि बाकी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

आईडीबीआई बैंक की याचिका खारिज, एनसीएलटी की शानदार जीत, एनसीएलटी की दो सदस्यीय पीठ ने मुंबई पीठ द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा

नई दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलटी) ने सोमवार को आईडीबीआई बैंक की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया गया था। एनसीएलटी की दो सदस्यीय पीठ ने मुंबई पीठ द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा और आईडीबीआई बैंक को देनदार की याचिका को खारिज करने की स्वतंत्रता प्रदान की। हालांकि, प्राधिकरण ने आईडीबीआई बैंक को दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की धारा 10ए में उल्लिखित अवधि से परे चूक के लिए नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के बाद आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू होने के बाद सरकार ने कंपनियों की मदद के लिए आईबीसी में विशेष प्रावधान शामिल किया था। इस विवाद में जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (जील) और आईडीबीआई बैंक के बीच हो रही उत्पन्नता और भुगतान की चूकों के बारे में बहस है। सीआईआरपी की धारा 10ए के अनुसार, चूक के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए उससे एक वर्ष की अवधि तक कोई आवेदन दायर नहीं किया जा सकता है। सिटी नेटवर्क्स ने 150 करोड़ रुपये के ऋण के लिए अपनी गारंटी को जील के लिए उधारने में मदद के रूप में प्रदान किया था, लेकिन उन्होंने चूक की है।

भारत में मोटर वाहनों की खुदरा बिक्री में छह प्रतिशत की वृद्धि

नई दिल्ली

बाजार में ग्रामीण क्षेत्रों का प्रदर्शन शहरी क्षेत्रों की तुलना में बेहतर रहा

भारत में वित्त वर्ष 2024-25 में मोटर वाहन की खुदरा बिक्री सालाना आधार पर छह प्रतिशत बढ़कर 2,61,43,943 इकाई हो गई है। यह जानकारी वाहन डीलरों के एक संगठन ने सोमवार को जारी एक बयान में दी। बाजार में ग्रामीण क्षेत्रों का प्रदर्शन शहरी क्षेत्रों की तुलना में बेहतर रहा।

वाहन डीलरों के संगठन के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में यात्री वाहनों, दोपहिया और तिपहिया वाहनों की बिक्री में वृद्धि देखी गई है। ग्रामीण बाजारों में दोपहिया वाहनों की बिक्री में आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो शहरी क्षेत्रों से अधिक है। इसके साथ ही तिपहिया वाहनों की ग्रामीण बिक्री में नौ प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।

वाइन डीलर संगठन के अध्यक्ष ने बयान में बताया कि मोटर वाहनों के खुदरा क्षेत्र में मजबूती देखने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 सरकार के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकता है। वाहनों की बिक्री में ग्रामीण क्षेत्रों में और बढ़ोतरी होने की खबर भविष्य में स्थिरता की ओर इशारा कर सकती है।

उन्होंने अपने बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 ने वास्तव में दिखाया कि भारत का मोटर वाहन खुदरा क्षेत्र कितना लचीला हो सकता है, इस वर्ष मुख्य आकर्षण ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन रहा। दोपहिया वाहनों के क्षेत्र में ग्रामीण बाजारों में आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो शहरी क्षेत्रों की वृद्धि से काफी अधिक है। यात्री वाहन क्षेत्र में ग्रामीण बिक्री वृद्धि आठ प्रतिशत जबकि शहरी क्षेत्रों में यह तीन प्रतिशत रही। वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में पिछले वित्त वर्ष में तिपहिया वाहनों की बिक्री पांच प्रतिशत बढ़कर 12,20,981 इकाई हो गई।

वहीं वित्त वर्ष 2024-25 में तिपहिया वाहनों की ग्रामीण बिक्री में नौ प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जबकि शहरों में बिक्री में कोई वृद्धि नहीं हुई। पिछले वित्त वर्ष में वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री मामूली घटकर 10,08,623 इकाई रह गई, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह 10,10,324 इकाई थी।

वहीं ट्रैक्टर की बिक्री सालाना आधार पर एक प्रतिशत घटकर 8,92,410 इकाई रह गई जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह 8,83,095 इकाई रही थी।

हालांकि मार्च में यात्री वाहनों का पंजीकरण वार्षिक आधार पर छह प्रतिशत बढ़कर 3,50,603 इकाई हो गया। मार्च 2024 में 15,35,398 इकाइयों की तुलना में दोपहिया वाहनों की बिक्री मार्च 2025 में दो प्रतिशत घटकर 15,08,232 इकाई रह गई।

दुनिया भर के बाजारों में भारी गिरावट

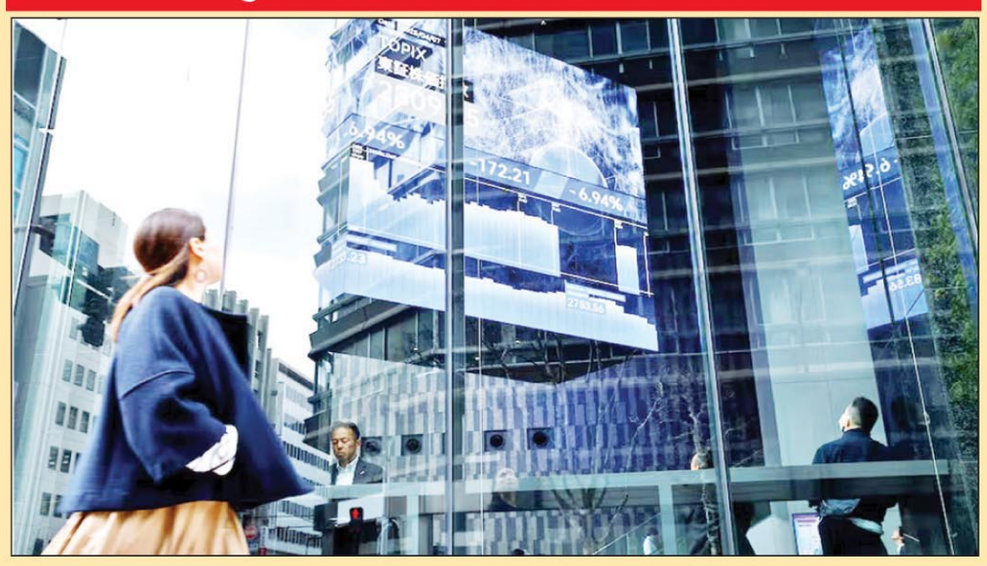

टोक्यो में गिरते हुए शेयर बाजार के पास से गुजरती हुई एक महिला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने की घोषणा के साथ ही दुनिया भर के बाजारों में भारी गिरावट आई है।

भारत में निजी इक्विटी निवेश में गिरावट, रियल एस्टेट में प्रवाह कमजोर

कार्यालय और गोदाम परिसंपत्तियों में निवेश की भारी गिरावट भी दर्ज की गई

नई दिल्ली

भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में निजी इक्विटी निवेश में तीन प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, जिसका एक रियल स्टेट सलाहकार ने अपनी ताजा जानकारी में दावा किया है। वित्त वर्ष 2024-25 में इस गिरावट के साथ पीई निवेश कुल 3.7 अरब अमेरिकी डॉलर रहा है, जो पहले के वित्त वर्ष की तुलना में थोड़ी कमी का अंक साबित होता है। रियल स्टेट के सलाहकार ने इस गिरावट की वजह के रूप में वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और भू-राजनीतिक अस्थिरता का जिक्र किया है, जो विदेशी निवेशकों की गतिविधियों में कमी के साथ विनम्रता बनाता है।

पिछले वित्त वर्ष में पीई निवेश की ज्यादातर हिस्सेदारी विदेशी निवेशकों के पास थी, जो 84 प्रतिशत तक थी, जबकि घरेलू निवेशकों की हिस्सेदारी 16 प्रतिशत रही। इस समय कार्यालय और गोदाम परिसंपत्तियों में निवेश की भारी गिरावट भी दर्ज की गई है, जो निजी इक्विटी निवेश के साथ संबंधित है। गोदाम परिसंपत्तियों में पीई निवेश में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसने आवास और कार्यालय संपत्तियों में स्थानांतरण में गिरावट का कारण बना है। वित्त वर्ष 2024-25 में हाइब्रिड सौदों की हिस्सेदारी 42 प्रतिशत रही है, जिसमें इक्विटी और ऋण निवेश में क्रमश: 37 प्रतिशत और 21 प्रतिशत की गिरावट आई है। इस तरह कुल संदर्भ में रियल एस्टेट सेक्टर में निजी इक्विटी निवेश में गिरावट के साथ वृद्धि और संविदानिक गतिविधियों में संकेत है कि वित्तीय स्थिरता की दिशा में तेजी हो सकती है।

ग्लोबल मार्केट से जबरदस्त गिरावट के संकेत, एशियाई बाजारों भी जोरदार गिरावट

नई दिल्ली

ग्लोबल ट्रेड वॉर की आशंका के कारण दुनिया भर के बाजारों में कोहराम मचा हुआ है। ग्लोबल मार्केट से जबरदस्त कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान बड़ी गिरावट का शिकार होकर बंद हुए। डाउ जॉन्स फ्यूचर्स भी जबरदस्त कमजोरी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजारों में भी पिछले सत्र के दौरान 5 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई। एशियाई बाजार में भी चौतरफा सुनामी का माहौल बना हुआ है।

अमेरिका की नई टैरिफ पॉलिसी के कारण दुनिया भर के शेयर बाजारों में मचे हड़कंप के आने वाले दिनों में भी जारी रहने के आसार हैं। पिछले सत्र के कारोबार के दौरान अमेरिकी बाजार में चौतरफा बिकवाली होती रही। बिकवाली के दबाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ दो दिन के कारोबार में ही अमेरिका में निवेशकों को 5 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। पिछले सत्र के दौरान एसएंडपी 500 इंडेक्स 322.44 अंक यानी 5.97 प्रतिशत टूट कर 5,074.08 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह नैस्डेक ने 948.58 अंक यानी 5.73 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 15,602.03 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। डाउ जॉन्स फ्यूचर्स भी फिलहाल 1,021.62 अंक यानी 2.67 प्रतिशत की गिरावट के साथ 37,293.24 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है।

अमेरिका की तरह ही यूरोपीय बाजार में भी पिछले सत्र के दौरान लगातार दबाव बना रहा। एफटीएसई इंडेक्स 419.76 अंक यानी 5.21 प्रतिशत फिसल कर 8,054.98 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह सीएसी इंडेक्स ने 324.03 अंक यानी 4.45 प्रतिशत की गिरावट के साथ 7,274.95 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा डीएएक्स इंडेक्स 1,075.67 अंक यानी 5.21 प्रतिशत की जबरदस्त कमजोरी के साथ 20,641.72 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

एशियाई बाजारों में भी निराशा का माहौल बना हुआ है। एशिया के 9 बाजारों में से 7 के सूचकांक गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। थाईलैंड और इंडोनेशिया के स्टॉक एक्सचेंज में छुट्टी होने की वजह से सेट कंपोजिट इंडेक्स और जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 837 अंक यानी 3.65 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 22,122 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह कोस्पी इंडेक्स 117.69 अंक यानी 4.77 प्रतिशत टूट कर 2,347.73 अंक के स्तर तक पहुंच गया है। हैंग सेंग इंडेक्स में जोरदार गिरावट आई है। फिलहाल यह सूचकांक 2,437.82 अंक यानी 10.67 प्रतिशत लुढ़क कर 20,411.99 अंक के स्तर तक गिर गया है। इसी तरह ताइवान वेटेड इंडेक्स 2,069.64 अंक यानी 9.72 प्रतिशत की गिरावट के साथ 19,228.58 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। इसके अलावा स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 302.73 अंक यानी 7.91 प्रतिशत टूट कर 3,523.13 अंक के स्तर पर, शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 211.84 अंक यानी 6.77 प्रतिशत फिसल कर 3,130.17 अंक के स्तर पर और निक्केई इंडेक्स 2,096.35 अंक यानी 6.21 प्रतिशत की गिरावट के साथ 31,684.23 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

इंटर मियामी को टोरंटो एफसी ने 1-1 की बराबरी पर रोका

नई दिल्ली

फोर्ट लॉडरडेल, फ्लोरिडा में रविवार रात लियोनेल मेसी की इंटर मियामी और फेडेरिको बेर्नार्डेस्की की टीम टोरंटो एफसी के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 से ड्रॉ समाप्त हुआ।

गए मुकाबले में मेसी और फेडेरिको बेर्नार्डेस्की ने अपनी अपनी टीमों के लिए एक-एक गोल किए। इस ड्रॉ के साथ इंटर मियामी (4-0-2, 14 अंक) ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में पहले स्थान से फिसल गई, जबकि टोरंटो एफसी (0-4-3, 3 अंक) ने एक मुश्किल मुकाबले से अंक हासिल किया।

पूरी ताकत के साथ उतरी इंटर मियामी, फिर भी जीत नहीं मिली

इंटर मियामी की इस नाकामी को और निराशाजनक इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि टीम में लियोनेल मेसी के साथ लुइस सुआरेज, जॉर्डी अल्बा और सर्जियो बुस्केट्स जैसे दिग्गज खिलाड़ी शुरुआत से ही मैदान पर मौजूद थे। बावजूद इसके टीम दो बार गोल करने के बाद भी स्कोरबोर्ड पर बढ़त नहीं बना सकी, क्योंकि एक गोल को ऑफसाइड और दूसरे को फाउल करार देकर खारिज कर दिया गया। हालांकि, मेसी ने हाफ टाइम से ठीक पहले पांचवें मिनट की इंजरी टाइम में जवाबी हमला करते हुए टेलास्को सेगोविया की पास पर बॉक्स के बाहर से बाएं पैर से शानदार गोल कर स्कोर 1-1 कर दिया। यह मेसी का इस सीजन एमएलएस में तीसरा और सभी प्रतियोगिताओं में कुल छठा गोल रहा।

पहले टोरंटो ने मारा गोल, फिर मेसी ने दिलाई बराबरी

दूसरे हाफ की शुरुआत में, 47वें मिनट में लोरेंजो इन्सिन्ये के क्रॉस पर बेर्नार्डेस्की ने शानदार कंट्रोल दिखाते हुए दो डिफेंडरों से घिरे होने के बावजूद गोल कर टोरंटो को 1-0 की बढ़त दिलाई।

न्यूज ब्रीफ

बैडमिंटन कोच रेप के आरोप में गिरफ्तार

बेंगलुरु। यहां एक 16 साल की नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार के आरोप में एक बैडमिंटन कोच को

गिरफ्तार किया गया है। इस कोच पर आरोप है कि उसने प्रशिक्षण सत्र के दौरान ही इस छात्रा को अपना शिकार बनाया। पुलिस ने इस मामले के पॉक्सो के तहत दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी कोच का मोबाइल भी जब्त किया है। पुलिस को उसके फोन में कथित तौर पर 13 से 16 साल की उम्र की आठ लड़कियों के अश्लील वीडियो भी मिले हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। यह सामने आया है कि आरोपी लड़की से उसके प्रशिक्षण सत्र के दौरान संपर्क करता था, उसे अपने घर पर बुलाता था और उसके साथ बलात्कार करता था। उसने कथित तौर पर इन घटनाओं को अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया। आरोप है कि उसने पीड़ित छात्रा को धमकाया था कि इस बारे में किसी को न बताए। इससे छात्रा डर गई थी पर लगातार उत्पीड़न के बाद उसने मां को बताया। इसके बाद इस कोच की हरकत का खुलासा हुआ। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार एक महिला ने एक शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि महिला की बेटी के साथ बैडमिंटन के कोच ने बलात्कार किया है। इस मामले में आरोपी को पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज करके कार्रवाई की गई है। आरोपी को शनिवार को गिरफ्तार किया गया और बाद में अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी (एसीएमएम) अदालत के समक्ष पेश किया गया।

चैंपियंस ट्रॉफी खेलने का अवसर नहीं मिलने से अब भी दुखी हैं सिराज

अहमदाबाद। आईपीएल में गुजरात टाइटन्स की ओर से शानदार प्रदर्शन कर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी में शामिल नहीं किये जाने से अब भी दुखी हैं। तब ये कहकर सिराज को शामिल नहीं किया गया था कि वह नई गेंद से प्रभावी गेंदबाजी नहीं कर पाते हैं। वहीं आईपीएल में सिराज ने अपने प्रदर्शन से इसे गलत साबित कर दिया है। सिराज को अब तक दो मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला है। अवार्ड समारोह में सिराज अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाये और उन्होंने कहा, जब आप अपने घरेलू मैदान पर आते हैं, तो यह एक अलग ही बात होती है। परिवार भी देख रहा होता है और इससे आपको आत्मविश्वास भी मिलता है। वहीं पिछले सात सत्र में आरसीसी की ओर से खेलने के दौरान ये बात नहीं थीं। टीम बदलने के बाद मैंने अपनी गेंदबाजी, क्षेत्ररक्षण और मानसिकता में जो काम किया है, उससे मुझे सहायता मिल रही है। इसके बाद सिराज ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए चयन नहीं होने को लेकर कहा, शुरुआत में मुझे बेहद निराशा हुई पर इसके बाद मैंने अपने को समझाया और अपनी मानसिकता, अपनी फिटनेस बेहतर करने पर ध्यान दिया। अब मैं अपनी गेंदबाजी का आनंद ले रहा हूं। सिराज ने साथ ही कहा, जब आपका चयन राष्ट्रीय टीम के लिए) नहीं होता है, तो दुख तो होता ही है पर इसके बाद मैंने आईपीएल पर ध्यान दिया और अब इसका लाभ मुझे मिल रहा है।

क्लार्क ने यशस्वी और सैमसन की जोड़ी को शानदार बताया

मुम्बई । ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने आइपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों

यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन की जोड़ी की जमकर प्रशंसा की है। क्लार्क ने कहा है कि ये दोनो किसी भी मैच को पलट सकते हैं। क्लार्क ने कहा, 'जायसवाल शुरुआती मैच में असफल होने के कारण पंजाब के खिलाफ बल्लेबाजी के दौरान ज्यादा सतर्क थे। कुछ अच्छे शॉट्स लगाने से उनका मनोबल बढ़ा जिससे टीम तेजी से आगे बढ़ी। वह मैदान के चारों ओर शॉट मारता है। उसे लेग साइड पसंद है, लेकिन कीपर के ऊपर से ऊपर की ओर शॉट मारना और उसका कवर ड्राइव उसके पास सभी शॉट हैं। अगर वह शुरुआत में संयम से खेले और कुछ गेंदें और पहले ओवर में जमीनी शॉट लगाये तो विरोधी टीम के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर सकता है। उन्होने कहा, 'राजस्थान रॉयल्स पहले से अलग टीम नजर आयी है। उसकी सलामी जोड़ी विस्फोटक है। उसके बल्लेबाज काफी अच्छे हैं। वहीं भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने युवा रियान पराग की जमकर प्रशंसा की ओर कहा, 'मुझे वाकई लगता है कि राजस्थान रॉयल्स के लिए पंजाब के खिलाफ मैच में रियान पराग की पारी काफी अहम थी। ये सही है कि उन्हें यशस्वी ने उन्हें अच्छी शुरुआत दी पर बाद में पराग ने स्कोर आगे बढ़ाया।

चार मैचों में लगातार हार पर बोले विटोरी हमें पता है इसके क्या नतीजे हो सकते हैं

हैदराबाद

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल 2025) में लगातार चार मैच हार चुकी सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) की टीम के हेड कोच डेनियल विटोरी ने अपने टॉप ऑर्डर के एग्रेसिव स्टाइल का बचाव किया है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि बल्लेबाजों को परिस्थितियों का सम्मान करना होगा और यह समझना होगा कि विरोधी टीमें एसआरएच के टॉप-3 बल्लेबाज़ों के खिलाफ काफी रणनीति बनाकर उतर रही हैं। एसआरएच को रविवार रात गुजरात टाइटन्स ने 7 विकेट से हरा दिया। यह आईपीएल 2025 में एसआरएच की लगातार चौथी हार थी। हैदराबाद में गुजरात टाइटंस के खिलाफ एसआरएच की बैटिंग एक बार फिर बिखर गई। टीम ने 20 ओवर में 152/8 का स्कोर बनाया, जिसे गुजरात ने सिर्फ 16.4 ओवर में तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया। मैच के बाद विटोरी ने कहा, हम जानते हैं कि हमारा खेलने का तरीका काम करेगा, लेकिन हमें परिस्थितियों का सम्मान करना होगा। ये चीज हम सही से नहीं कर पा रहे हैं। विरोधी टीमें हमारे टॉप-3 बल्लेबाजों के खिलाफ काफी सोच-समझकर गेंदबाज़ी कर रही हैं और हम उसका तोड़ नहीं निकाल पा रहे।

कोच विटोरी ने बताया कि यह पिच टिपिकल हैदराबाद विकेट जैसी नहीं थी और बल्लेबाज़ों के लिए खेलना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने कहा, हम 160-170 के स्कोर का टारगेट कर रहे थे। हमें लगा कि अगर बल्लेबाज़ जमकर खेलें और अंत में तेज़ी से रन बटोरें, तो यह स्कोर संभव है। लेकिन हम करीब 20 रन पीछे रह गए।

एसआरएच ने इस सीजन की शुरुआत धमाकेदार तरीके से की थी, जब उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 286 रन बनाए थे। लेकिन उसके बाद टीम का प्रदर्शन लगातार गिरा है। विटोरी ने कहा, मैं नहीं मानता कि पैट कमिंस कभी घबराते हैं और मैं भी ऐसा नहीं करता। लेकिन हम यह समझते हैं कि लगातार चार मैच हारना हमारे सीजन को मुश्किल बना सकता है।

उन्होंने आगे कहा, पिछले चार मैचों में हम अपनी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल पाए हैं - चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग। खासकर फील्डिंग में हमारा प्रदर्शन बहुत खराब रहा है।

सिराज आईपीएल में 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ियों में शामिल, पर्पल कैप की दौड़ में दूसरे नंबर पर पहुंचे

हैदराबाद। गुजराज टाइटंस के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने यहां सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हुए मुकाबले में चार विकेट लेकर एक अहम उपलब्धि हासिल की है। सिराज अब इस लीग में 100 विकेट लेने वाले 26 वें गेंदबाज बन गये है। इससे पहले भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव, संदीप शर्मा, हर्षल पटेल, मोहित शर्मा, मोहम्मद शमी, आशीष नेहरा, आर विनय कुमार, जहीर खान और शार्दुल ठाकुर ने ही 100 विकेट लिए हैं। सिराज अपने इस प्रदर्शन के साथ ही सबसे अधिक विकेट के लिए मिलने वाली पर्पल कैप के भी दावेदार बनकर उभरे हैं। सिराज ने सनराइजर्स के खिलाफ 17 रन देकर 4 विकेट लिए और हैदराबाद को 152 रन पर रोक दिया। अब उनके नाम पर 4 मैचों में 13 की औसत के साथ 9 विकेट हो गए हैं। वह पर्पल कैप की दौड़ में दूसरे नंबर पर हैं। सिराज ने गत दिनों जब आरसीबी के खिलाफ 19 रन देकर 3 विकेट ली थी तो टीम कोच आशीष नेहरा ने उनकी जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि सिराज ने दिखाया कि वह नई गेंद के साथ कितने खतरनाक हो सकते हैं। उनकी फिटनेस और गति में सुधार प्रभावशाली है। इसके अलावा, भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने भी सिराज की आक्रामकता की तारीफ की है। बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी से पहले मोर्कल ने कहा कि सिराज 100 फीसदी देने वाला खिलाड़ी है। वह पूरे दिन दौड़कर गेंदबाजी कर सकता है और टीम के लिए हमेशा संघर्ष करता है।

धोनी बोले, आईपीएल से संन्यास का फैसला फिटनेस के आधार पर करुंगा

चेन्नई

चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा है कि अभी वह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से संन्यास नहीं ले रहे और इस मामले में कोई भी फैसला अपनी फिटनेस के आधार पर करेंगे। धोनी ने कहा कि वर्तमान सत्र के बाद अपनी फिटनेस का आंकलन करने के बाद ही वह अगले सत्र में खेलने पर कोई फैसला करेंगे। वहीं आईपीएल से संन्यास के बारे में पूछे गए सवाल पर धोनी ने कहा कि मैं अभी भी आईपीएल में खेल रहा हूं और इसी पर ध्यान दे रहा हूं। मैं अभी 43 साल का हूं और एक बार में एक साल तक की ही बात कर सकता हूं। जब यह सत्र खत्म होगा, तब तक मैं 44 साल का हो जाऊंगा। इसलिए, मेरे पास यह तय करने के लिए अभी करीब 10 महीने हैं कि मैं अगले साल खेल सकता हूं या नहीं।

उन्होंने कहा कि ये मेरे चाहने या न चाहते की जगह फैसला इस पर आधारित होगा कि मेरा शरीर क्या चाहता है। यह शरीर है जो आपके लिए फैसले लेता है। मैं खेल जारी रख सकता हूं या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मैं शारीरिक रूप से कैसा महसूस करता हूं। अभ मैं इस बात पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रहा हूं कि इस सत्र में क्या करना होगा। वहीं इस सत्र में धोनी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा और वह बल्लेबाजी में भी निचले क्रम पर उतरे।

धोनी ने कहा कि खेल में मिली सफलता कड़ी मेहनत और अनगिनत व्यक्तियों के समर्थन का परिणाम हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल के दिनों से ही मेरे माता-पिता, मेरे खेल शिक्षक और वे लोग जिनके साथ मैंने अपने शुरुआती मैच खेले, सभी ने इसमें भूमिका निभाई। यहां तक कि टेनिस-बॉल क्रिकेट ने भी मुझे कई चीजें सिखाईं, हालांकि इसमें भी कुछ अजीब चीजें भी हैं। उन्होंने कहा कि असफलताएं खेल का हिस्सा हैं पर जो मायने रखता है वह वापसी करने की क्षमता है। धोनी ने कहा कि जीवन में कोई बड़ा या छोटा अवसर नहीं होता। सभी मायने रखते हैं। मैं कई लोगों का आभारी हूं। कुछ को तो यह भी नहीं पता होगा कि मैं उनका आभारी हूं।

सूजूका में जापानी ग्रांट प्री रेस में जीत का जश्न मनाते हुए

सूजूका में जापानी ग्रांट प्री रेस में जीत के बाद साथियों के साथ जश्न मनाते हुए रेड बुल के मैक्स वर्सटेपन।

रुद्रांक्ष ने शूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जीता गोल्ड, बाबूता सातवें स्थान पर

नई दिल्ली

पूर्व विश्व चैंपियन रुद्रांक्ष बलासाहेब पाटिल ने रविवार को अर्जेंटीना में चल रहे आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं, भारत के ही अर्जुन बाबूता फाइनल में सातवें स्थान पर रहे।

शानदार शुरुआत से अंत तक छाए रहे रुद्रांक्ष

रुद्रांक्ष ने फाइनल की शुरुआत से ही बढ़त बना ली थी। पहले सीरीज में 53.2 अंक जुटाकर वह टॉप पर रहे और पूरे फाइनल के दौरान अपनी पकड़ बनाए रखी। हंगरी के इस्तवान पेनी एक बार उन्हें चुनौती देने की स्थिति में आए, लेकिन रुद्रांक्ष ने जल्द ही वापसी करते हुए गोल्ड मेडल पक्का कर लिया। पेनी को सिल्वर से संतोष करना पड़ा।

बाबूता नहीं दिखा सके दम, जल्दी हुए बाहर

दूसरी ओर अर्जुन बाबूता का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। उन्होंने शुरुआती पांच शॉट्स में सिर्फ 50.4 अंक हासिल किए। हालांकि एक 10.5 स्कोर ने उन्हें पहले एलिमिनेशन से बचा लिया, लेकिन अगली सीरीज में वह बाहर हो गए और सातवें स्थान पर रहे।

चीन और अर्जेंटीना के निशानेबाजों ने दी टक्कर

चीन के वांग होंघाओ ने कई बार एलिमिनेशन से खुद को बचाया, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल की दौड़ में वह अर्जेंटीना के एम.जे. गुटिरेज़ से पिछड़ गए। गुटिरेज़ ने घरेलू दर्शकों के सामने कांस्य पदक अपने नाम किया।

क्वालिफिकेशन में भारतीयों का दबदबा

इससे पहले क्वालिफिकेशन राउंड में बाबूता और रुद्रांक्ष ने क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर रहते हुए फाइनल में प्रवेश किया। बाबूता ने 634.5 और रुद्रांक्ष ने 633.7 स्कोर किया।

किरण अंकुश जाधव ने भी टॉप आठ में जगह बनाई लेकिन वह आरपीओ (रैंकिंग पॉइंट्स ओनली) के तहत खेल रहे थे, जिससे वह फाइनल में जगह नहीं बना सके।

एफसी गोवा से हार कर भी बेंगलुरु एफसी बनी बाजीगर, पहुंची फाइनल में

गोवा

एफसी गोवा ने रविवार रात अपने घरेलू मैदान फतोर्दा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले गए इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) 2024-25 सेमीफाइनल के दूसरे चरण में बेंगलुरू एफसी को 2-1 से हरा दिया लेकिन ब्लूज ने बेहतर गोल अंतर के आधार पर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। बेंगलुरू एफसी के पक्ष में गोल अंतर 3-2 रहा, क्योंकि उसने अपने घर में खेले गए डबल-लेग सेमीफाइनल के पहले मैच में गौर्सा को 2-0 से हराया था।

अनुभवी स्ट्राइकर सुनील को निर्णायक गोल करने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। जीत के बावजूद गौर्सा के बाहर होने से स्पेनिश हेड कोच मैनोलो मार्क्वुएज जरूर निराश होंगे, क्योंकि गोल अंतर के आधार पर उनकी टीम का सफर इस सीजन में समाप्त हो गया है।

वहीं, ब्लूज भले ही मैच हारे लेकिन वे अपने घरेलू प्रदर्शन के आधार पर फाइनल में पहुंच गए हैं और इससे स्पेनिश हेड कोच जेरार्ड जारागोजा निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे।

मैच का पहला गोल 49वें मिनट में आया, जब स्थानापन्न स्पेनिश मिडफील्डर बोर्जा हेरारा ने एफसी गोवा को शुरुआती बढ़त दिलाते हुए स्कोर 1-0 (कुल गोल अंतर 1-2) कर दिया। पेनल्टी बॉक्स के ठीक बाहर मिली फ्री-किक पर बोर्जा हेरारा ने करारा लेफ्ट फुटर शॉट लगाकर गेंद को बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के अंदर पहुंचा दिया जबकि बेंगलुरू एफसी के अनुभवी गोलकीपर गुरप्रीत संधू बचाव करने में नाकाम रहे। यह इस सीजन में हेरारा का छठा गोल है।

88वें मिनट में अल्बेनियाई स्ट्राइकर अर्मांडो सादिकु ने इस सीजन में अपना दसवां गोल करके एफसी गोवा को शुरुआती बढ़त को दोगुना करते हुए स्कोर 2-0 (कुल गोल अंतर 2-2) कर दिया।

लेफ्ट-बैक आकाश सांगवान ने बायीं तरफ से क्रॉस डालकर गेंद को सेंटर किया, जिस पर सादिकु ने हैडर से गेंद को बॉटम राइट कॉर्नर के अंदर पहुंचा दिया जबकि बेंगलुरू एफसी के अनुभवी गोलकीपर गुरप्रीत संधू बचाव नहीं कर पाए।

स्टॉपेज टाइम के दौरान 90+2वें मिनट में स्थानापन्न स्ट्राइकर सुनील छेत्री ने इस सीजन का अपना 14वां गोल करके बेंगलुरू एफसी को कुछ राहत पहुंचाते हुए स्कोर स्कोर 1-2 (कुल गोल अंतर 3-2) कर दिया।

कॉर्नर किक के दौरान नामग्याल भूटिया ने बॉक्स के अंदर बायीं तरफ से दाहिनी तरफ से क्रॉस डाला, जिस पर सुनील ने बॉक्स के अंदर से हैडर लगाकर गेंद को गोल जाल में उलझा दिया।

गेंद पर ज्यादा नियंत्रण एफसी गोवा का 62 फीसदी रहा। गौर्स ने सात प्रयास भी किए, जिनमें से तीन शॉट टारगेट पर रखे लेकिन पूरे हाफ के दौरान दबदबा बनाए रखने के बावजूद गोल नहीं कर पाए। वहीं, गेंद पर 38 फीसदी कब्जा रखने वाली बेंगलुरू एफसी की ओर से किए गए दोनों प्रयास टारगेट पर नहीं थे, लिहाजा गोल नहीं आया। हालांकि ब्लूज ने बेहतर रणनीति के साथ खेलते हुए मेजबान टीम को ज्यादा अवसर न देकर अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया।

दुनिया में हर साल 300 मिलियन टन से ज्यादा प्लास्टिक तैयार हो रहा है। हमारे जीवन में घुसपैठ कर चुके प्लास्टिक का एक खतरनाक पहलू यह है कि इससे तैयार कोई भी उत्पाद पूरी तरह से नष्ट नहीं होता। प्लास्टिक को किसी भी तरीके से नष्ट या खत्म करने अथवा कहीं डंप करने के बावजूद उसका घातक असर पर्यावरण में मौजूद रहता है। प्लास्टिक कचरे को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए वैज्ञानिक पिछले कुछ दशकों से गंभीर प्रयासों में जुटे हैं और हाल ही में उन्हें इस दिशा में बड़ी सफलताएं भी मिली हैं।

प्लास्टिक को खत्म करने की जुगत...

अब पैसों से खरीदें खुशी...

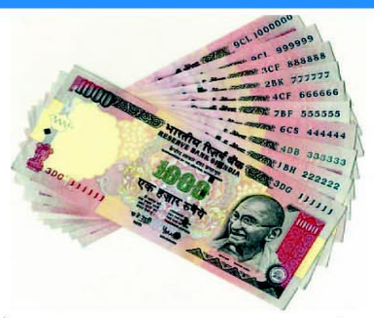

पैसा जो काम की सारी चीजे दिला सकता है, लेकिन एक चीज नहीं दिला सकता, वो है खुशी। ऐसा बड़े बुजुर्गों का मानना था। लेकिन एक नए शोध ने इस कहावत को झुठला दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पैसे के सही इस्तेमाल से आप खुशियां भी खरीद सकते हैं। शोध में कहा गया है कि अगर आप अपने व्यक्तित्व के अनुसार पैसा खर्च करते हैं, तो इससे आपको वास्तव में खुशी का अहसास होगा। साथ ही अपनी जरूरतों के मुताबिक खर्च करने से आपकी जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। ब्रिटेन स्थित कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के शोध में पता चला है कि पैसा और संपूर्ण व्यक्तित्व के बीच हमेशा से ही कमजोर संबंध रहा है। शोध वास्तविक लेन-देन के आंकड़ों को खंगालते हुए इस तथ्य की नई जमीन तैयार करता है कि खर्च हमारी खुशी को बढ़ा सकता है। बशर्ते इसका इस्तेमाल सही वस्तुओं और सेवाओं पर किया जाए जो हमारे व्यक्तित्व के लिए उपयुक्त होने के साथ ही हमारी मनोवैज्ञानिक जरूरतों को भी पूरा करती हों।

तनाव कम करने में मददगार है चॉकलेट खाना

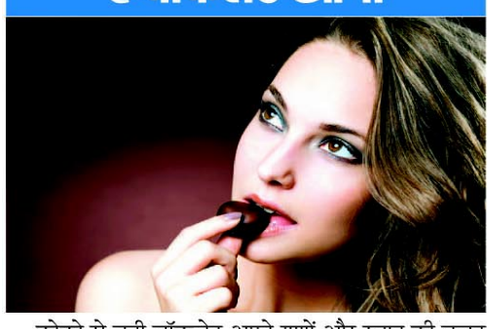

कोको से बनी चॉकलेट अपने गुणों और स्वाद की वजह से लगभग 100 सालों से ही टेस्टी ट्रिंक्स और चॉकलेट बार के रूप में फेमस रही है। चॉकलेट प्रेमी जानते हैं कि चॉकलेट मूड अच्छा रखने के साथ ही तनाव भी दूर करती है। इसके अलावा इसे खाने के और क्या-क्या फायदे हो सकते हैं इनके बारे में जानेंगे...।

दिल के लिए लाभदायक

साल 2010 में हुए एक सर्वे से पता चला है कि यह हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, इसलिए चॉकलेट खाने से दिल की बीमारियों के होने की संभावना काफी कम हो जाती है। वहीं यूरोपीय सोसायटी ऑफ कार्डियोलॉजी द्वारा किए गए शोध में पाया गया है कि ज्यादा मात्रा में चॉकलेट खाने से दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है। मूड अच्छा बनाए चॉकलेटऑस्ट्रेलियाई रिसर्चर्स द्वारा साल 2015 में किए गए स्टडीज के अनुसार, कोको का इस्तेमाल हेल्दी लोगों में शांति और संतोष बढ़ाता है। इसके अलावा यह मेंटली परफॉर्मेंस को बेहतर कर थकान कम करने में मदद करता है।

प्लास्टिक कचरा गलियों-सड़कों-खेतों से लेकर नदियों और समुद्रों तक में यह प्रवाहित हो रहा है। आप धरती के किसी भी कोने में चले जाएं प्लास्टिक कचरा जरूर दिखेगा। समुद्रों में जिस तरह से प्लास्टिक कचरा बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए यह आशंका प्रबल हो रही है कि वर्ष 2050 तक समुद्र में यह इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि मछलियों से ज्यादा तादाद में प्लास्टिक कचरा मौजूद होगा। इससे निबटने के लिए वैज्ञानिक पिछले कुछ दशकों से गंभीर प्रयासों में जुटे हैं और हाल ही में इस दिशा में एक बड़ी कामयाबी मिली है। क्योटो यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम एक बार कचरे के ढेरों में कुछ उम्मीदें तलाश रही थी। उन्होंने प्लास्टिक को कुतरनेवाले कुछ माइक्रोब देखे। करीब 250 सैंपल्स पर पांच वर्षों तक शोध करने के बाद उन्होंने कुछ बैक्टीरिया को अलग किया, जो पीईटी यानी पॉली-इथिलीन टेरेफ्थालेट में जीवित रह सकते हैं। दरअसल, 'पीईटी' एक कॉमन प्लास्टिक है, जिसका इस्तेमाल बोतलों और अनेक सिंथेटिक कपड़ों के निर्माण में किया जाता है। प्लास्टिक खानेवाले माइक्रोब्स का धरती पर अस्तित्व कई वर्षों पहले ही खोज लिया गया था। लेकिन, हालिया खोजी गई चीजों में कुछ महत्वपूर्ण फर्क पाये गये हैं। जैसे एक शोध में यह साबित हुआ है कि इस कार्य के लिए उपयोगी माइक्रोब्स को आसानी से पैदा किया जा सकता है।

एंजाइम की भी पहचान

वैज्ञानिकों ने 'आइडियोनेला सेकेनसिस' नामक यह एंजाइम की भी पहचान की है जो 'पीइटी' को नष्ट करने में सक्षम पाया गया है। सभी जीवित चीजों में एंजाइम्स होते हैं, जिनका इस्तेमाल जरूरी केमिकल रिएक्शंस को गति देना होता है। कुछ एंजाइम्स हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं। इन जरूरी एंजाइम्स के बिना शरीर कुछ खास प्रकार के भोजन से पोषक चीजें नहीं हासिल कर सकता है। उदाहरण के तौर पर लैक्टोज नहीं पचा पाने वाले लोगों में एंजाइम नहीं होते, जो डेयरी उत्पादों में पाये जोने वाले लैक्टोज शुगर को तोड़ते हैं। कोई भी इन्सान सेल्यूलोज नहीं पचा सकता, जबकि माइक्रोब्स ऐसा कर सकते हैं। 'आइडियोनेला सेकेनसिस' में कुछ ऐसे सक्षम एंजाइम पाये गये हैं, जिन्हें बैक्टीरिया पर्यावरण में पैदा करते हैं। क्योटो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने बैक्टीरिया के डीएनए में जीन की पहचान की है, जो पीईटी को पचानेवाले एंजाइम के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार वे ज्यादा से ज्यादा एंजाइम बनाने में सक्षम पाये गये हैं और ये दर्शाते हैं कि महज ये एंजाइम ही इन पीईटी को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं।

वास्तविक रिसाइकलिंग

इस शोध ने प्लास्टिक रिसाइकलिंग और परिशोधन का एक नया नजरिया दिया है। मौजूदा समय में अधिकांश प्लास्टिक बोतलों को वास्तविकता में रिसाइकिल नहीं किया जाता है। इन्हें पिघला कर और कुछ सुधार करके प्लास्टिक के कठोर उत्पाद बनाये जाते हैं। लेकिन पैकेजिंग कंपनियां ज्यादातर फ्रेश प्लास्टिक का इस्तेमाल करती हैं, जिन्हें पेट्रोलियम पदार्थों से हासिल होनेवाले रसायनों से बनाया जाता है। पीईटी-डाइजेस्टिंग एंजाइम्स ने ही प्लास्टिक के रिसाइकल की वास्तविक राह तैयार की है। कूड़े-कचरे के साथ मिला कर इनके जरिये सभी प्रकार के प्लास्टिक बोतलों और अन्य आइटम्स को वास्तविक रूप से खत्म किया जा सकता है। इस प्रकार इन घातक रसायनों से आसानी से निबटा जा सकता है। साथ ही वास्तविक रिसाइकलिंग सिस्टम के जरिये फ्रेश प्लास्टिक बनाया जा सकता है।

प्लास्टिक खाने वाले वर्म्स

वैज्ञानिकों ने पशुओं की आंत में पाये जानेवाले एक ऐसे बैक्टीरिया की भी पहचान की है, जिसे प्लास्टिक को जैविक तरीके से खत्म करने में कामयाब पाया गया है । इससे पर्यावरण को प्लास्टिक के घातक असर से बचाया जा सकेगा। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और चीन की बेहांग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कुछ ऐसे मीलवर्म की तलाश की है, जो अनेक प्रकार के पॉलिस्टिरीन और स्टाइरोफोम को खाने और उसे पचाने में सक्षम पाये गये हैं। इन वर्म्स की आंत में प्लास्टिक जैविक तरीके से पच जाता है और इसका पूरी तरह से अपघटन हो जाता है। इस शोध से प्लास्टिक से पैदा होने वाली वैश्विक समस्याओं को खत्म करने को एक नयी दिशा मिलने की उम्मीद जगी है।

पानी में घुलने वाला प्लास्टिक

इटली की एक कंपनी ऐसा प्लास्टिक बना रही है, जो पानी में घुल सकता है। यह कंपनी चुकंदर से निकलने वाले कचरे से प्लास्टिक बनाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि चुकंदर के उत्पादन से निकलने वाले बाइ-प्रोडक्ट से बनने वाला प्लास्टिक पर्यावरण के लिए कोई खतरा नहीं बनेगा। इसके अलावा पेट्रोलियम पदार्थों से बनने वाले प्लास्टिक पर निर्भरता को कम करने में कामयाबी मिल सकती है। इटली की एक छोटी कंपनी 'बायो ऑन' जैव प्लास्टिक के क्षेत्र में नवीनतम प्रयास का प्रतिनिधित्व कर रही है। इटली के शहर मिनेर्बियो में सबसे बड़ी चीनी उत्पादक कंपनी 'को प्रो बी' चुकंदन से चीनी बनाती है। चुकंदर से चीनी बनने के बाद यह कंपनी कचरे के तौर पर जिन चीजों को फेंक देती है, 'बायो ऑन' उसी से प्लास्टिक का निर्माण करती है।

बैक्टीरिया कुतरेंगे बोतल

वैज्ञानिकों ने ऐसे बैक्टीरिया तैयार किये हैं, जो प्लास्टिक कचरे को खत्म करेंगे। शुरू में इन्हें रिसाइकलिंग सेंटर में कचरे के ढेरों में डाला जाएगा, जहां ये डंप किये गये प्लास्टिक बोतलों को कुतरने का काम करेंगे। हाल ही में इसका परीक्षण किया गया है और विकसित किये गये बैक्टीरिया को इस कार्य के लिए उपयुक्त पाया गया है। दरअसल, प्लास्टिक को मुख्य रूप से पेट्रोलियम पदार्थों से निकलने वाले कृत्रिम रेजिन से बनाया जाता है। रेजिन में अमोनिया और बेंजीन को मिला कर प्लास्टिक के मोनोमर बनाये जाते हैं। इसमें क्लोरीन, फ्लोरिन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के अणु होते हैं। लंबे समय तक अपघटित न होने के अलावा प्लास्टिक अनेक अन्य प्रभाव छोड़ता है, जो इनसान की सेहत के लिए हानिकारक हैं।

मिलावटी दूध से कैसे बचें...?

देश के तीन में से दो लोग डिटर्जेंट, कॉस्टिक सोडा, यूरिया और पेंट वाल दूध पीते हैं। देश में बिकने वाला 68 प्रतिशत दूध देश की खाद्य उत्पाद नियंत्रक संस्था एफएसएसएआई के मापदंडों पर खरा नहीं उतरता।

देश के 200,000 गांव से दूध एकत्रित करके बेचा जाता है। मिलावटी दूध से बचने का सबसे सटीक तरीका दूध उबालना है, जिससे सभी बैक्टीरिया मर जाते हैं। पिछले साल अमेरिका सरकार की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2016 में बढ़ती आबादी के अनुपात में दूध की खपत में 5 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ यह 62.75 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। मिलावटी दूध का शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। यूरिया, कॉस्टिक सोडा और इसमें मौजूद फोरमेलिन से गैस्ट्रोएंट्रटिटिस से लेकर इम्पेयरमेंट, दिल के रोग, कैंसर और मौत तक हो सकती है।

पानी की मिलावट

डिटर्जेंट से पाचन तंत्र की गड़बडियां और फूड पॉयजनिंग हो सकती है। उच्च एल्केलाइन से शरीर के तंतु क्षतिग्रस्त और प्रोटीन नष्ट हो सकते हैं। इन खतरों को देखते हुए बचाव जरूरी है। एफएसएसएआई के ताजा सर्वेक्षण के मुताबिक, दूध में पानी की मिलावट सबसे ज्यादा होती है, जिससे इसकी पौष्टिकता कम हो जाती है। अगर पानी में कीटनाशक और भारी धातुएं मौजूद हों तो ये सेहत के लिए खतरा है। दूध को उबालना इसका हल है।

इसके साथ ही 46 प्रतिशत सैंपल लो सॉलिड नॉट फैट की श्रेणी के पाए गए, जिसकी मुख्य वजह पानी की मिलावट है। गरमी के मौसम में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते स्किमड मिल्क पाउडर के 548 नमूनों में से 477 नमूनों में ग्लूकोज पाया गया। दूध के रख-रखाव और पैकेजिंग के समय साफ-सफाई का ध्यान न रखे जाने की वजह से आस पास प्रयोग हुआ डिटर्जेंट दूध में चला जाता है। कई बार यह जान बूझ कर डाला जाता है। 8 प्रतिशत नमूनों में डिटर्जेंट पाया गया।

इस तरह करें जांच

- **पानी:** ढलान वाली सतह पर दूध की एक बूंद डालें। शुद्ध दूध की बूंद धीरे-धीरे सफेद लकीर छोड़ते हुए जाएगी, जबकि पानी की मिलवाट वाली बूंद बिना कोई निशान छोड़े बह जाएगी।
- **स्टार्च:** लोडीन का टिंक्चर और लोडीन सॉल्यूशन में कुछ बूंदे डालें, अगर वह नीली हो जाएं तो समझे कि वह स्टार्च है।
- **यूरिया:** एक चम्मच दूध को टेस्ट ट्यूब में डालें। उसमें आधा चम्मच सोयाबीन या अरहर का पाउडर डालें। अच्छी तरह से मिला लें। पांच मिनट बाद, एक लाल लिटमस पेपर डालें, आधे मिनट बाद अगर रंग लाल से नीला हो जाए तो दूध में यूरिया है।
- **डिटर्जेंट:** 5 से 10 एमएल दूध को उतने ही पानी में मिला कर हिलाएं। अगर झाग बनता है तो इसमें समझिए डिटर्जेंट है।
- **सिन्थेटिक दूध:** सिन्थेटिक दूध का स्वाद कड़वा होता है, उंगलियों के बीच रगड़ने से साबुन जैसा लगता है और गर्म करने पर पीला हो जाता है। सिन्थेटिक दूध में प्रोटीन की मात्रा है या नहीं, इसकी जांच दवा की दुकान पर मिलने वाली यूरीज स्ट्रिप से की जा सकती है। इसके साथ मिली रंगों की सूची दूध में यूरिया की मात्रा बता देगी।

ज्यादा ठंडा पानी न पीएं...

गर्मी के मौसम का सबसे ज्यादा प्रभाव शरीर पर पड़ता है और हम इसे ठंडा रखने के लिए कई उपाय भी करते हैं. ठंडा पानी पीना सबसे सरल उपाय होता है लेकिन क्या आप जानते हैं आपकी यह आदत आपके दिल को नुकसान पहुंचा सकती है। ठंडा पानी भोजन की पाचन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है क्योंकि इससे रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं। इससे पाचन की प्रक्रिया धीमी पड़ने से खाना ठीक से नहीं पचता और हमें इसके पोषक तत्व भी नहीं मिल पाते। बर्फ का पानी या तेज ठंडा पानी पीने से हृदय की गति कम हो जाती है। ठंडा पानी वेगस तंत्रिका को उत्तेजित करता है। वेगस तंत्रिका 10वीं कपाल तंत्रिका है और यह शरीर के स्वायत्त तंत्रिका प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो शरीर के अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करती है। वेगस तंत्रिका हृदय की गति को कम करने में मध्यस्थता करती है और ठंडा पानी इस तंत्रिका को उत्तेजित करता है जिसके कारण हृदय की गति कम हो जाती है।

फिल्मों में तकनीक का ओवरडोज...

63वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स की घोषणा हो चुकी है। हॉलीवुड की तरह अब बॉलीवुड की फिल्मों में भी तकनीक का कमाल देखा जा सकता है। किसी फिल्म में यह वाकई कमाल लगता है तो कहीं-कहीं ओवरडोज भी महसूस होता है। कहानी की मांग के बिना जबरन ठूंसा गया यह ओवरडोज फिल्म को फ्लॉप भी करा देता है। इस बारे में पिछले कई साल से फिल्म टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे तन्मय मसूरकर कहते हैं कि हम फिल्म टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निरंतर कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यह तो फिल्मकारों की जिम्मेदारी है कि वे उसका कितना सटीक उपयोग करते हैं। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि फिल्म निर्माण में साउंड से लेकर स्पेशल इफेक्ट्स तक हर टेक्नोलॉजी एक सही सब्जेक्ट की मांग करती है। फिल्म के सब्जेक्ट में बेवजह इसका इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं है।

सब्जेक्ट की मांग: बात वाजिब है। इसके लिए हॉलीवुड फिल्मों का अच्छा उदाहरण दिया जा सकता है। वहां ज्यादातर फिल्में ही ऐसी बनती हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी के उपयोग की पूरी संभावना रहती है। और जहां सब्जेक्ट इस बात की डिमांड नहीं करता, वहां के फिल्मकार इस बात से साफ बचते हैं। इसके लिए टाइटैनिक का एक उदाहरण देना ही काफी होगा। इस तीन घंटे से ज्यादा लंबी रोमांटिक फिल्म के सब्जेक्ट में रोमांस इस कदर भरा हुआ है कि इसमें फिल्म टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फइसके कैनवस को विस्तृत रंग देता है। भारतीय फिल्मकारों को भी इसी तरह से सोचना चाहिए। बाहुबली में इसका उपयोग दर्शनीय लगता है। पर पीकू में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी सिर्फ निरर्थक होगी। क्योंकि पीकू एक सब्जेक्ट बेस्ड फिल्म है।

तकनीक एक हथियार: संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी भी ऐसी फिल्म है, जिसमें वीएफएक्स सहित दूसरी तकनीक का काफी इस्तेमाल किया गया। भंसाली टेक्नोलॉजी के हिमायती हैं। वे कहते हैं कि फिल्म मेकिंग में टेक्नोलॉजी के बढ़ते महत्व से मैं भी इंकार नहीं करता हूं। मगर यह फिल्म के हर सीन की जरूरत के मुताबिक होना चाहिए। बाजीराव मस्तानी के युद्ध दृश्यों में मैंने टेक्नोलॉजी का खुलकर उपयोग किया। पर इसका यह मतलब नहीं है कि लड़ाई के सीन को हमने सिर्फ वीएफएक्स स्टुडियो में फिल्माया है। इसके वॉर सीन की हमने एक महीने तक शूटिंग की थी। क्योंकि मेरा यह मानना है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ फिल्म के सुंदर फिल्माकंन के लिए जरूरी है। वरना फिल्म तो डायरेक्टर का मीडियम होती है। टेक्नोलॉजी तो महज उसके काम का एक हथियार है। स्पेशल इफेक्ट्स तकनीक की मदद से इसके सारे फ्रेम को और ज्यादा भव्य बनाया गया।

पुरानी फिल्में हैं उदाहरण: आज ज्यादातर फिल्मों में ही तकनीक का कमाल देखने को मिल जाता है। हां, छोटे बजट की फिल्में इस तकनीक से थोड़ा बचती हैं, क्योंकि वीएफएक्स और दूसरी तकनीक का इस्तेमाल खर्चीला है। देखा जाये तो फिल्मों के जन्म के साथ ही फिल्म तकनीक को बढ़ावा मिलने लगा था। कभी महबूब खान, के.आसिफ, वी.शांताराम, राज कपूर आदि दिग्गज फिल्मकारों की नजर फिल्म के तकनीकी पक्ष पर भी होती थी। एक बार झनक-झनक पायल बाजे की शूटिंग से पहले वी.शांताराम के छायाकार जी.बालकृष्ण ने एक खास तरह के लेंस का हवाला देते हुए उनसे कहा था कि यदि यह मिल जाए तो अगली फिल्म की शूटिंग में बहुत सुविधा हो जाएगी। वी.शांताराम यानी अण्णा के जेहन में यह बात बैठ गई। उन दिनों वह लंदन जाने वाले थे। लौटते वक्त वह उस लेंस को अपने साथ ले आए थे।

बड़जात्या नहीं लेते सहारा

वर्तमान में ग्लोबल हो चुके फिल्मोद्योग ने समय के साथ ताल मिलाकर तकनीक के हर बदलाव को बखूबी अंजाम देना सीख लिया है। लेकिन फिल्मकार सूरज बड़जात्या तकनीक के ज्यादा गुलाम नहीं हैं। हालांकि उनकी फिल्म 'प्रेम रतन धन पायो' में उन्होंने न चाहते हुए भी इस तकनीक का उपयोग किया है। इस फिल्म के छायाकार वी. मानिकनंदन इससे पहले रा-वन, ओम शांति ओम, मैं हूं ना, ये जवानी है दीवानी जैसी कई बड़ी फिल्मों का छायांकन कर चुके हैं। मानिकनंदन के मुताबिक सूरज उन निर्देशकों से भिन्न हैं जो अपने दृश्यों को संभालने के लिए तकनीक का सहारा लेते हैं। वे कहते हैं कि हम भारतीय छायाकार विदेशी तकनीशियनों से किसी भी मामले में कमतर नहीं हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि ये सारा कमाल हम बहुत सीमित साधन में कर दिखाते हैं।'

कैसी-कैसी तकनीक

डीआई तो सिर्फ एक तकनीक का नाम हुआ। वरना आज फिल्म की शूटिंग के दौरान चिप, वीएफएक्स, क्रोमा, एनीमेशन, थ्रीडी, ऑन लाइन एडिटिंग या स्मोक आदि ढेरों तकनीकी शब्दों को सुनना बेहद रूटीन सा हो गया है। मजेदार बात तो यह है कि ऐसी ढेरों तकनीक ने एक्शन से लेकर म्यूजिक रिकॉर्डिंग तक हर जगह अपनी जगह बना ली है। आज इस तकनीक की मदद से फिल्मों की भव्यता को एक बुलंदी दी जा रही है। स्पेशल इफेक्ट्स के सारे साधन स्टुडियो में उपलब्ध होते हैं।

मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश शर्मा द्वारा अजय त्यागी के लिए ईको प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट एवं पीएस : गड़चुक, कटाबाड़ी मस्जिद के पास, कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-35 से मुद्रित एवं **गुड लक पब्लिकेशंस, हाउस नं. 30, डी. नेउग पथ, डोना प्लैनेट के नजदीक, एबीसी, जीएस रोड गुवाहाटी-5 से प्रकाशित।**
संपादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 94350-14771, 97070-14771 ● **कार्यकारी संपादक : प्रदीप शील ● सहयोगी संपादक : रवि शंकर चौधरी ● फोन : 0361-2960054 (संपादकीय)** e-mail : viksitbharatsamacharghy@gmail.com, **(सभी विवाद सिर्फ गुवाहाटी न्याय क्षेत्र के अधीन)**